गुरुवार 18 दिसंबर 2025 ■ मूल्य 3.00 ■ वर्ष 03 ■ अंक 272 ■ पृष्ठ 08

गौतमबुद्ध नगर

JBT

www.thejbt.com

# जनभावना टाइम्स

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 प्रदूषण अब राष्ट्रीय समस्या | 07 लियोनेल मेस्सी को उम्मीद, भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल होगा | यह सिर्फ फिल्म नहीं, हर देशभक्त के लिए लव लेटर, धुरंधर... 08

# सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए

## दिल्ली की सीमा पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करें: उच्चतम न्यायालय

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रण को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों को बंद करने, खाली बैठे निर्माण श्रमिकों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को यातायात सुगम बनाने और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने समेत कई अहम मुद्दों पर विचार किया।

उच्चतम न्यायालय ने एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करें, ताकि शहर में यातायात भीड़ में कमी लाई जा सके। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण के संकट को 'हर साल सामने आने वाली समस्या' करार दिया और इस खतरे से निपटने के लिए कारगर एवं व्यावहारिक समाधानों का आह्वान किया। हालांकि, न्यायालय ने नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के निर्देश में दखल देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सर्दी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में इस फैसले में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर वाहनों की भीड़ को कम करने की कोशिश के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करें।

पीठ ने खास तौर पर एमसीडी से एक हफ्ते के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने को कहा कि क्या यातायात प्रवाह को सुचारु बनाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इन टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने केवल प्रोटोकॉल बनाने के बजाय मौजूदा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आइए इस खतरे के व्यावहारिक और कारगर समाधानों के बारे में सोचें।

उन्होंने कहा कि हालांकि निवारक उपाय मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन लगातार कमजोर रहा है। न्यायालय ने प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों से रोजी-रोटी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों का तत्काल सत्यापन करे और यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाए। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि लगभग ढाई लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से अब तक लगभग 7,000 का सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने पीठ को भरोसा दिलाया कि वित्तीय सहायता सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।

हालांकि, पीठ ने इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी के प्रति आगाह करते हुए कहा कि 'ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रमिकों के खातों में अंतरित राशि गायब हो जाए या किसी अन्य खाते में चली जाए। उसने दिल्ली सरकार से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर भी विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या हर सर्दियों में बढ़ जाती है।

उसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और उन्हें मजबूत करने का निर्देश दिया। पीठ ने सीएक्यूएम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन, यातायात प्रबंधन और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन देने जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा। उसने स्पष्ट किया कि टुकड़ों में किए गए उपायों से संकट का समाधान नहीं होगा। इसी के साथ पीठ ने पर्यावरणविद् एमसी मेहता की ओर से दायर जनहित याचिका को अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया। उसने दोहराया कि इस याचिका पर पूरे साल हर महीने कम से कम दो बार सुनवाई होनी चाहिए।

# निर्माण मजदूरों को 10 हजार की आर्थिक सहायता देगी सरकार : कपिल मिश्रा

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार ने ग्रैप की पाबंदियों के दौरान बंद रहे निर्माण कार्यों की वजह से श्रमिकों की आय की क्षतिपूर्ति करने के लिए पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सचिवालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के अहम निर्णयों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए चल रही पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत सत्यापन भी लगातार जारी है। इस व्यवस्था में दो चरण शामिल हैं- पहला पंजीकरण और दूसरा सत्यापन। श्रम विभाग पूरी क्षमता और गंभीरता के साथ इस कार्य में जुटा हुआ है। जैसे-जैसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होती जाएगी, उसी क्रम में लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। मिश्रा ने बताया कि वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रम विभाग ने सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से सीमित की जाएगी जबकि शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। मंत्री मिश्रा ने कहा कि यह दिशा-निर्देश आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। इनमें अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग, वन विभाग और जल बोर्ड आदि शामिल हैं। उन्होंने अपील की कि सभी संस्थान कार्य समय में लचीलापन अपनाएं, कार पुलिंग को प्रोत्साहित किया जाए और निजी वाहनों के उपयोग को कम से कम किया जाए।

इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है और अनुपालन न होने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 एवं 16 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा कि आज जिस तरह की राजनीति की जा रही है, वह देश की दिल्ली के लिए उचित नहीं है। जब उनकी सरकार थी, तब उनके मंत्री कभी सड़कों पर दिखाई नहीं दिए और प्रदूषण को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया गया। आज दिल्ली में जो टूटी सड़कें, गड्ढे, धूल और गंदगी दिखाई दे रही है, वह पांच महीने की नहीं बल्कि 13 वर्षों की लापरवाही का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि 13 वर्षों में न तो दिल्ली की सड़कें ठीक हो सकीं, न फुटपाथ सुधर पाए और न ही ग्रीन कवर बढ़ सका। आज दिल्ली को जो प्रदूषण विरासत में मिला है, उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। आज दिल्ली सरकार का हर एक मंत्री, हर एक विधायक और मुख्यमंत्री पूरी निष्ठा से दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार संकल्पित है कि जो काम वे 13 साल में नहीं कर पाए, उसे हम करके दिखाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है लेकिन हम सही दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग संवेदनशील समय में राजनीतिक प्रदूषण फैला रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपील की कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सभी को मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहयोग करना चाहिए।

## संक्षिप्त खबरें

### संसद ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के प्रावधान वाले विधेयक को दी मंजूरी

**नई दिल्ली।** संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने दावा किया कि इस विधेयक के प्रावधानों से देश के बीमा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्यसभा ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इसे ध्वनि मत से स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही सदन ने विपक्ष द्वारा पेश विभिन्न संशोधनों को खारिज कर दिया। इन संशोधनों में विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था।

### गुजरात: मोरबी जिले में ट्रक ने तीर्थयात्रियों को रौंदा, 4 लोगों की मौत

**मोरबी (गुजरात)।** गुजरात के मोरबी जिले में बुधवार को एक ट्रक ने तीर्थयात्रियों को रौंद दिया जिसमें चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। घायल तीर्थयात्री को मोरबी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपाधीक्षक प्रतिपालसिंह जाला ने बताया कि पीड़ित तीर्थयात्रा के लिए द्वारका जा रहे थे, तभी सुबह करीब छह बजे मालिया गांव और जामनगर के बीच यह दुर्घटना हुई। जाला ने पत्रकारों को बताया कि राज्य राजमार्ग पर पैदल चल रहे तीर्थयात्रियों को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। उनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया।

### मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या: मुठभेड़ में संदिग्ध मारा गया

**चंडीगढ़।** मोहाली में 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रमोटर की हत्या के एक संदिग्ध को बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पंजाब के तरन तारन जिले के नौशेहरा पन्नुआं के रहने वाले हरपिंदर उर्फ मिड्डू का पुलिस की टीम पीछा कर रही थी और इस दौरान हुई गोलीबारी में वह घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका उपचार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि संदिग्ध कई जघन्य अपराधों में शामिल था और उसका आपराधिक इतिहास गंभीर है। मोहाली में एक निजी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालाचौरिया को सोमवार को गोली मार दी गयी थी।

### ईडी का ड्रीम-इलेवन से जुड़े अनुराग के ठिकानों पर छापा

**उन्नाव।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापा मारा। अनुराग ड्रीम इलेवन से जुड़े थे। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और कथित सट्टेबाजी से जुड़े मामले में की गई। दस वाहनों में पहुंची ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने एक साथ अनुराग के पैतृक गांव भितरेपार खजूर और नवाबगंज कस्बे में छापा मारा। लेकिन अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं थे। टीम ने कई घंटों तक उनके ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की और संपत्ति से जुड़े कागजात खंगाले। इसके बाद टीम ने कस्बे में रहने वाले चाचा नपेन्द्र नाथ द्विवेदी से पूछताछ कर उनके घर की छानबीन की।

# परमाणु ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित

**नई दिल्ली।** लोकसभा में देश की कुल ऊर्जा जरूरतों में परमाणु ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा विधेयक बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने और इसके उपयोग को गैर विद्युत क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए है। विधेयक निजी क्षेत्र के द्वार नाभीकीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खोलेगा।

केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज सतत दोहन और भारत के रुपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025 या शांति विधेयक (सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर चली लम्बी चर्चा के बाद केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनों का आधुनिकीकरण करना और इस क्षेत्र को सबके लिए सुलभ बनाना है।

उन्होंने कहा कि यह कोई नया विधेयक नहीं है। हमने इसमें केवल कुछ पहलुओं में संशोधन किया है। यह विधेयक देश के विकास पथ को नई दिशा देगा। विधेयक की धारा 9 व्यक्तियों को नवाचार और अनुसंधान करने की अनुमति देती है। एक अन्य धारा सरकार को सुरक्षा कारणों से कुछ कंपनियों की भागीदारी प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

डॉ सिंह ने कहा कि कई विपक्षी दल विधेयक को पूरी तरह पढ़े बिना ही उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार ने विधेयक को ठीक से परिभाषित किया है और इसमें शामिल निजी पक्षों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी है। विधेयक सुरक्षा, संरक्षा, सुरक्षा उपायों, गुणवत्ता आश्वासन और आपातकालीन तैयारियों से संबंधित तंत्रों को मजबूत करता है।

# पीएम अबी अहमद द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया

**अदीस अबाबा/नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान, 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद द्वारा अदीस अबाबा के अदीस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी, जो 16-17 दिसंबर को इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर हैं, ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने इसे अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री डॉ. अबी और इथियोपिया के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उनकी पहलों की सराहना की। राष्ट्र निर्माण में ज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय शिक्षकों के लिए एक सदी से अधिक समय से इथियोपिया की प्रगति और विकास में योगदान देना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्राप्त करके सम्मानित महसूस हो रहा है। मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह पुरस्कार उन सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है और इस सम्मान से नवाजे जाने पर 14 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पुरस्कार भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी में एक मील का पत्थर है और वैश्विक दक्षिण के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

# सेना को अमेरिका से मिले तीन अपाचे हेलीकॉप्टर, पश्चिमी सीमा पर होंगे तैनात

**नई दिल्ली।** भारतीय सेना को तीन एएच-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का आखिरी बैच अमेरिका से मिल गया है, जिससे राजस्थान के जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में उसके छह एयरक्राफ्ट का बेड़ा पूरा हो गया। अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव एयरलाइंस के एएन-124 सामरिक एयर लिफ्टर विमान से सीधे एरिजोना से हिंडन एयरबेस तक लाया गया है। ये अपाचे जोधपुर एयर बेस से वायु सेना के एलसीएच प्रचंड के साथ मिलकर काम करेंगे।

भारतीय सेना के लिए साल 2020 में 80 करोड़ डॉलर में 06 अपाचे हेलीकॉप्टरों का सौदा अमेरिका से किया गया था। समय पर आपूर्ति मिलने की उम्मीद में सेना ने पिछले साल 15 मार्च को जोधपुर में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की पहली स्क्वाड्रन भी बना ली थी। तीन अपाचे एएच-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का पहला बैच पिछले साल 22 जुलाई को भारत पहुंचा था। शेष तीन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति में देरी की वजह बोइंग कंपनी की सप्लाई चेन बाधित होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पिछले साल अमेरिकी यात्रा पर सेना को अपाचे हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति में हो रही देरी का मुद्दा उठाया गया था, इसके बावजूद डिलीवरी में करीब 15 माह की देरी हुई है। सेना के लिए अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है।

दोनों स्क्वाड्रन एक ही जगह होने से लड़ाकू अमेरिकी 'अपाचे' और स्वदेशी 'प्रचंड' की जुगल जोड़ी आसमान में नया गुल खिलाएगी। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर में 16 एंटी टैंक मिसाइल दागकर उसके परखच्चे उड़ा सकता है। इसे दुश्मन पर बाज की तरह हमला करके सुरक्षित निकल जाने के लिए बनाया गया है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी बंदूकों से 30 एमएम की 1,200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। अपाचे एक बार में 2.45 घंटे तक उड़ान भर सकता है।

ये हेलीकॉप्टर उन्नत सुविधाओं से लैस है, जिनमें लॉन्ग रडार, हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट और अन्य सटीक प्रहार प्रणालियां शामिल हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से बख्तरबंद खतरों मुकाबला करने में प्रभावी होंगे। अपाचे को दुनिया भर में सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। हेलफायर मिसाइल, 70 एमएम रॉकेट और 30 एमएम चेन गन से लैस यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के कवच, बंकर और एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है।

### ट्राई ने IRDI नियामित संस्थाओं के लिए 1600-सीरीज नंबर का दिया निर्देश

**नई दिल्ली।** देश में बढ़ते साइबर क्राइम और फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बीमा नियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियामित सभी संस्थाओं को 15 फरवरी 2026 तक सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए 1600-सीरीज नंबर उपयोग करने का आदेश दिया है।

### अरुणाचल: आग में जलकर भाई-बहनों की मौत

**इटानगर।** अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के तेजू में बुधवार को पियो कॉलोनी में लगी भीषण आग के चलते आठ और पंद्रह वर्ष की आयु के भाई-बहनों की जलकर मौत हो गई।

तेजू के पुलिस अधीक्षक थुप्तेन जांबा ने बताया कि यह घटना आज सुबह घटी, जब आग ने तीन आवासीय भवनों को अपनी चपेट में ले लिया। ये सभी पुराने एसपीटी (स्पेशल परेड) प्रकार के क्वार्टर थे। बताया जाता है कि भवनों की बनावट के कारण आग तेजी से फैली और लोगों को बचने का बहुत कम समय मिला। दमकल और पुलिस दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के घरों में नहीं फैली।

# अश्लील सामग्री के कारण 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाया प्रतिबंध: सरकार

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 43 ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए सख्त कानूनी ढांचा मौजूद है। इन नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को किसी भी ऐसे कंटेंट का प्रसारण न करने का दायित्व है, जो कानूनन प्रतिबंधित हो।

डॉ. मुरुगन ने बताया कि आईटी नियम, 2021 के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी) के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आयु-आधारित वर्गीकरण, शिकायत निवारण के लिए तीन-स्तरीय तंत्र तथा अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा तय की गई है।

नियमों के उल्लंघन पर मध्यस्थों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट भी समाप्त हो सकती है। एक अन्य प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्मों के प्रमाणन के लिए गठित वैधानिक संस्था है और ओटीटी कंटेंट को इसके दायरे में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

# मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर नई दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का किया उद्घाटन

**नई दिल्ली।** दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थापित अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली सरकार; डॉ. विकास कुमार, प्रबंध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह संग्रहालय 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से आम जनता के लिए खोला जाएगा। संग्रहालय का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह संग्रहालय मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा, जबकि सोमवार एवं सार्वजनिक अवकाशों के अवसर पर बंद रहेगा। अधिकाधिक आगंतुकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ₹10 प्रति व्यक्ति का नाममात्र प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है।

लगभग 12,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में विस्तृत इस संग्रहालय को प्रथम चरण में विश्व के प्रतिष्ठित मेट्रो संग्रहालयों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसमें उन्नत प्रदर्शन प्रणालियों एवं सहभागितापूर्ण (इंटरएक्टिव) अनुभव उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की ब्लू लाइन पर स्थित सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर होने के कारण यह संग्रहालय आगंतुकों के लिए सुगम रूप से सुलभ है। भारत मंडपम तथा सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख स्थलों के समीप स्थित होने से यह सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। संग्रहालय में मेट्रो ट्रेन संचालन का वास्तविक अनुभव प्रदान करने वाले सिमुलेटर, टनल बोरिंग मशीन एवं लॉन्चिंग गर्डर के कार्यशील मॉडल, तथा आगंतुकों के गेम खेलने एवं मेट्रो निर्माण प्रक्रिया को समझाने हेतु इंटरएक्टिव डिजिटल डिस्प्ले उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, क्विज शो स्क्रीन, सेल्फी प्वाइंट एवं स्मृति चिह्न (सुवेनियर) की दुकानें संग्रहालय के सहभागितापूर्ण वातावरण को और सुदृढ़ बनाते हैं, जबकि स्थायी मॉडल एवं प्रदर्शनियां मेट्रो प्रणाली के विभिन्न तकनीकी एवं प्रचालन पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं। संग्रहालय में मेट्रोमैन डॉ. ई. श्रीधरन पर आधारित एक समर्पित पैनल, एक मॉक मेट्रो सुरंग तथा ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली के प्रमुख स्थलों को दर्शाने वाले डायोरामा, गणमान्य व्यक्तियों के दौरों पर आधारित फोटो गैलरी तथा मेट्रो के इतिहास की प्रमुख उपलब्धियों से संबंधित पैनल, दिल्ली मेट्रो के विकास क्रम का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं।

कुल मिलाकर, संग्रहालय में 50 से अधिक पैनल, प्रदर्शनी, कियोस्क एवं मॉडल स्थापित किए गए हैं। भविष्य में द्वितीय चरण (फेज-11) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रदर्शनियों एवं नवाचारों को सम्मिलित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो संग्रहालय की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 2008 में हुआ था, जब भारत की सबसे उन्नत शहरी परिवहन प्रणाली की विकास यात्रा को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने का विचार परिकल्पित किया गया।

इसी क्रम में 31 दिसंबर 2008 को देश का प्रथम मेट्रो रेल संग्रहालय पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटित किया गया, जो उस समय संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी प्रकार का एकमात्र संग्रहालय था। राजधानी के नागरिकों को नववर्ष के उपहार स्वरूप समर्पित यह संग्रहालय शीघ्र ही यात्रियों एवं आगंतुकों के मध्य लोकप्रिय हो गया। पटेल चौक स्थित मेट्रो संग्रहालय में प्रतिवर्ष देश-विदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से लगभग 5,000 विदयार्थी भ्रमण हेतु आते थे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर नए दिल्ली मेट्रो संग्रहालय के उद्घाटन के साथ ही शौक स्थित मेट्रो संग्रहालय को अब बंद कर दिया गया है।

# एल्युमिनियम बर्तन उद्योग भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा : सीएम

**नई दिल्ली।** कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के सहयोगी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एल्युमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स (एफएआईएयूएम) की नेशनल गवर्निंग काउंसिल (एनजीसी) का आयोजन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में और भाजपा सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस राउंड टेबल राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के 25 राज्यों के व्यापारी नेता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि एल्युमिनियम बर्तन उद्योग भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने इसे किफायती, टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल एवं 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण योग्य उद्योग बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्यों के पूर्णतः अनुरूप है। उन्होंने कहा की यह बर्तन दादी-नानी के जमाने से उपयोग में लाए जा रहे हैं और हमेशा महत्वपूर्ण बने रहे गए। उन्होंने उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार एमएसएमई और स्वदेशी विनिर्माण को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र को भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एल्युमिनियम बर्तन उद्योग विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रवीन खंडेलवाल ने कहा समर्थन देता है। उन्होंने उद्योग को मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियानों का सशक्त आधार बताते हुए गुणवत्ता, मानकीकरण, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर निरंतर ध्यान देने का आह्वान किया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एल्युमिनियम बर्तन उद्योग 100 प्रतिशत मेक इन इंडिया होने के बावजूद अनेक नीतिगत और व्यावहारिक समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि फेडरेशन वर्ष 1991 से निरंतर कार्यरत है और आज देशभर में इसके लगभग 4,000 विनिर्माण यूनिट्स हैं, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। कार्यक्रम के अंत में फेडरेशन ने केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ निरंतर संवाद, नीति-समर्थन और उद्योग के संतुलित विकास के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

# फर्जी इनकम टैक्स रेड के जरिए 1 किलो सोने की चोरी करने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (मध्य रेंज) ने फर्जी इनकम टैक्स रेड स्क्वॉड बनाकर एक किलो से अधिक सोने की चोरी के मामले में वांछित चल रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से चोरी किया गया 130.162 ग्राम सोना और वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान . अंबेडकर नगर निवसी शेख अकरम (49) के रूप में हुई है। आरोपित थाना प्रसाद नगर के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 27 नवंबर को करोल बाग इलाके में स्थित एक ज्वैलरी मेकिंग वर्कशॉप के मालिक ने थाना प्रसाद नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि 5-6 अज्ञात व्यक्ति वर्कशॉप में घुसे। जिनमें से एक ने फर्जी दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जबकि चार अन्य लोग इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए थे।

आरोपितों ने शिकायतकर्ता और कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए, फर्जी तलाशी ली और करीब 1 किलो 1 ग्राम सोना चोरी कर लिया। जाते समय आरोपी वर्कशॉप में लगा सीसीटीवी डीवीआर भी साथ ले गए, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। मामले में पहले ही मध्य जिला पुलिस द्वारा पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जबकि शेख अक़रम फरार चल रहा था। पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आरोपित शेख अकरम अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार दक्षिण दिल्ली में ठिकाने बदल रहा है। इस पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार कलखंडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। 14 दिसंबर को टीम ने मल्होत्रा बी एंड बी,

सी.आर. पार्क में छापा मारकर आरोपित को दबोचा। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना जुर्म कबूल किया। तलाशी में उसके पास से 130.162 ग्राम चोरी का सोना और वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पुलिस के अनुसार, शेख अकरम करीब 16-17 साल पहले दिल्ली आया था और करोल बाग क्षेत्र में अलग-अलग ज्वैलरी मेकिंग की दुकानों पर काम करता रहा। फिलहाल वह एक ज्वैलरी शॉप में काम कर रहा था और अपने परिवार के साथ मदनगीर में रह रहा था। करीब 2-3 साल पहले उसका संपर्क मुख्य आरोपित और मास्टरमाइंड परमिंदर, जो एक सरकारी कर्मचारी है, से हुआ था। इसके बाद उसने करोल बाग की ज्वैलरी दुकानों से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं, जिसके आधार पर इस वारदात की साजिश रची गई। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और चोरी किए गए बाकी सोने की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

## संक्षिप्त खबरें

### दिल्ली : लूट के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज ने एक विशेष अभियान के तहत लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान गौतमपुरी निवासी मोमिन उर्फ मोबिन (31) के रूप में हुई है। आरोपित थाना न्यू उस्मानपुर में दर्ज लूट के मामले में वांछित था और उसे पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बुधवार को बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपित मोमिन उर्फ मोबिन चोरी-छिपे गौतमपुरी इलाके में रह रहा है। इसके बाद टीम ने स्थानीय स्तर पर सत्यापन किया और रिकॉर्ड खंगाले, जिससे पुष्टि हुई।पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपित को दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपित मोमिन उर्फ मोबिन अशिक्षित है और मजदूरी का काम करता है। वह लंबे समय से पुलिस से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

### 'बीड़ी' को लेकर व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में एक गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** पूर्वी जिले के पांडव नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना शशि गार्डन स्थित पं. राम प्रसाद बिस्मिल कैंप की मुख्य सड़क के पास हुई। जांच में मृतक की पहचान शशि गार्डन निवासी दीपक (28) के रूप में हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि रात करीब 1:24 बजे पांडव नगर थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। जिसमें सूचना दी गई कि शशि गार्डन बस स्टैंड, हनुमान मंदिर की ओर एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही एसआई लवकांत और एएसआई विपिन कुमार मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी मात्रा में खून फैला मिला। पूछताछ में पता चला कि घायल को पीसीआर वैन द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। एसआई लवकांत अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। शव के निरीक्षण में मृतक के माथे और दाहिनी आंख/चेहरे के आसपास गंभीर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद शव को अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया। घटना की सूचना पर क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पहुंची और घटनास्थल की जांच करने के बाद साक्ष्य जुटाए। मामले में पांडव नगर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित मनोज (32) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक दीपक के साथ बीड़ी/सिगरेट को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर हाथापाई हुई। जिसमें दीपक ने उसका गला पकड़ लिया।

# आरजू और अनमोल बिश्नोई गिरोह के पांच आरोपी गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात आरजू और अनमोल बिश्नोई -हैरी बॉक्सर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपित देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई तीन हत्याओं में शामिल रहे हैं और दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

स्पेशल सेल को पुख्ता सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ में इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या में शामिल एक आरोपित हाल ही में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में देखा गया है। इस इनपुट के बाद स्पेशल सेल ने गहन फील्डवर्क और तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल डेटा, लोकेशन और अन्य सुरागों की कड़ी से अहम जानकारियां जुटाई गईं। इसी दौरान पता चला कि गैंग के कई सदस्य अलग-अलग जत्थों में दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहले चरण में स्पेशल सेल की टीम ने रिंग रोड स्थित शांति वन के पास से कुंवरबीर, संतोष उर्फ कपिल खत्री और लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके अन्य साथी भी जल्द दिल्ली आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत रणनीति बदली और सराय काले खां बस स्टैंड के पास जाल बिछाकर पियूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में पियूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में 1 दिसंबर को हुए इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी हत्याकांड के मुख्य शूटर बताए जा रहे हैं। पियूष पिपलानी राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पंचकूला में हुई हत्या में भी मुख्य शूटर रहा है।

वहीं संतोष उर्फ कपिल खत्री अमृतसर में सितंबर 2025 में बार व रेस्टोरेंट मालिक अशुतोष महाजन उर्फ आशु की हत्या के मामले में वांछित था। कुंवरबीर इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी का ड्राइवर था, जबकि लवप्रीत सिंह हाल ही में जमानत पर छूटकर दोबारा गैंग के संपर्क में आया था।

स्पेशल सेल के अनुसार, आरोपितों के कब्जे से चार अवैध हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इन सभी को दिल्ली में इकट्ठा होकर किसी बड़े और गंभीर अपराध को अंजाम देने के निर्देश मिले थे। पुलिस की समय पर कार्रवाई से राजधानी में एक संभावित बड़ी वारदात टल गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गैंग को बड़ा झटका लगा है। पकड़े गए आरोपी कम से कम तीन हाई-प्रोफाइल हत्याओं में वांछित थे। उनसे पूछताछ जारी है और गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों के स्रोत और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

# सीयूईटी के बाद डीयू की दाखिला प्रक्रिया हुई अधिक पारदर्शी और जवाबदेह: कुलपति

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीयूईटी) लागू होने के बाद डीयू की दाखिला प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तार्किक, पारदर्शी और जवाबदेह हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा केंद्रीकृत प्रणाली के तहत अब हर स्टेकहोल्डर को प्रत्येक सीट की स्थिति की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। कुलपति ने बताया कि डीयू के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) के तहत हर आवंटन को सार्वजनिक किया जाता है और इसके लिए वैज्ञानिक व डेटा-आधारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि कम से कम आवंटन राउंड में अधिकतम सीटें भरने के उद्देश्य से कॉलेजों को अपनी सीट मैट्रिक्स पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। कुछ कॉलेजों में स्नातक कार्यक्रमों की खाली सीटों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि यह स्थिति सीयूईटी के कारण नहीं है।

डीयू दाखिला शाखा के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सीयूईटी से पहले भी सीटें खाली रहती थीं। वर्ष 2019 में, जब 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिले होते थे, तब कुल 70,735 उपलब्ध सीटों में से 68,213 ही भरी गई थीं और 3.56 प्रतिशत सीटें खाली रह गई थीं। कुलपति ने कहा कि सीयूईटी आधारित

दाखिलों के तहत इस वर्ष में कुल 71,642 सीटों के मुकाबले 72,229 दाखिले हुए हैं, यानी स्वीकृत क्षमता से 0.65 प्रतिशत अधिक।

उन्होंने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पहले कट-ऑफ आधारित प्रणाली में दाखिलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। कई मामलों में तय क्षमता से कई गुना अधिक दाखिले हो जाते थे, जिससे अव्यवस्था पैदा होती थी। प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि नए सिस्टम में कॉलेज यह तय कर सकते हैं कि वे किसी कोर्स में कितनी अतिरिक्त सीटें देना चाहते हैं। यह पूरा डेटा एल्गोरिदम (नुस्खे) के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिससे अधिक या कम दाखिलों की समस्या को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। साथ ही, प्रोग्राम की लोकप्रियता का अनुमानित विश्लेषण कर विश्वविद्यालय अपनी दाखिला नीति को और प्रभावी बना सकता है।

# ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल यूनिट ने एक बड़े ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए पांच और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह संगठित गिरोह चीनी सरगना के इशारे पर काम कर रहा था और देशभर में सैकड़ों लोगों को ठग चुका है। इससे पहले इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने बुधवार को बताया कि आरोपितों के कब्जे से मिले बैंकिंग दस्तावेज देशभर में एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कुल 1167 एफआईआर/शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर ठगी मामलों में भी शामिल रहा है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, 23 जून को दक्षिण-पूर्व की साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसमें पीड़ित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसे टेलीग्राम ग्रुप के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर रोजाना मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। 'आज खरीदो-कल बेचो' और आईपीओ रेटिंग जैसे फर्जी वादों के जरिए आरोपित ने पीड़ित से करीब दो महीनों में 47,23,015 की रकम विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली। जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की, तो उसे डराया-धमकाया गया और और अधिक पैसे की मांग की गई।पुलिस उपायुक्त ने बताया कि क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 31.45 लाख 'हर्षिता फर्नीचर्स एंड इंटीरियर्स' के करंट खाते में जमा कराए गए। इसके बाद 23.80 लाख 'बुबई इंस्टेंट शॉप ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड' के खाते में ट्रांसफर किए गए। जिसे एक शेल कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपितों ने अलग अलग बैंकों इंडसइंड, एचडीएफसी, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन और इक्विटास में कुल सात करंट अकाउंट खोलकर ठगी की रकम को इधर-उधर किया।

### नोएडा से चल रहा था फर्जी ट्रेडिंग ऑफिस

वहीं पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपित नोएडा में एक ऑफिस चलाकर निवेशकों को फर्जी ट्रेडिंग स्कीम में फंसाते थे। ये सभी आरोपित 'जैक' नामक हैंडलर के संपर्क में थे, जो आगे चीन में बैठे 'टॉम' नामक व्यक्ति के निर्देशों पर काम करता था। तकनीकी जांच में फर्जी सिम कार्ड और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पांच आरोपितों को दबोचा। पकड़े गए आरोपितों की पहचान हरियाणा निवासी मनजीत सिंह (28), सोनीपत निवासी मानश्वी दोचक (23), भिवानी निवासी सोमबीर (43), नजफगढ़ निवासी मनीष मेहरा (32) और कुरुक्षेत्र निवासी अतुल शर्मा (30) के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त के अनुसार जांच में इस गिरोह द्वारा इस्तेमाल की जा रही 14 फर्जी निवेश और ट्रेडिंग ऐप्स की पहचान की गई है, जिनके जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। वहीं इस मामले में अब तक कुल आठ आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोचा था। मामले में धन के लेन-देन की पूरी कड़ी खंगाली जा रही है और फरार आरोपितों की तलाश जारी है।

# चोरी और स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

## पुलिस ने 2 करोड़ के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किये बरामद

**नोएडा।** नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को दबोचा है जो धार्मिक पहचान बदलकर और भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि थाना फेस-1 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व मोबाइल फोन की चोरी और स्नेचिंग कर उनकी व उनके पार्ट्स की अन्तर्राज्यीय तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों फिरोज पुत्र जलाउद्दीन, फरदीन पुत्र शबाबुद्दीन, सलीम पुत्र जमील अहमद तथा दानिश पुत्र यासीन को को आज लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से सेक्टर-14 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से चोरी व स्नेचिंग के 60 आई फोन, 10 मल्टीमीडिया फोन, 28 आई पैड, 1 टैबलेट, 265 मोबाइल फोन के पार्ट्स, 1 टीवी डिवाइस (एप्पल), 1 स्कूटी बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये हैं। डीसीपी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के आस-पास क्षेत्रों में घूमघूमकर ऐसे स्थानों को चिह्नित करते थे, जहाँ लोगों की भीड़ अधिक रहती है। ऐसे स्थानों पर वे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चोरी व स्नेचिंग करते थे। इसके अलावा जहां जनसभाँ होती थीं, वहां अभियुक्त भीड़ में आम समर्थक बनकर शामिल हो जाते थे। हिंदू जनसभाओं में शक से बचने के लिए वे अपने मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम रख लेते थे, जिससे किसी को उन पर संदेह नहीं होता था। भीड़ का फायदा उठाकर वे महंगे और ट्रेंड में चल रहे आईफोन व स्मार्ट मोबाइल फोन आसानी से चोरी कर लेते थे, जिनकी बाजार में काफी मांग रहती है। चोरी किए गए मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स को मांग के अनुसार बेचकर वे अच्छा पैसा कमा लेते थे।

डीसीपी ने बताया कि पकडे गये आरोपियों से की गई गहन पूछताछ में जो खुलासे हुए, वो बेहद चैंकाने वाले थे। ये अपराधी न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर, बल्कि हापुड़, बुलंदशहर और मथुरा जैसे अन्य शहरों में भी सक्रिय थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे मॉल, जनसभाओं या धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। खुद को सामान्य दिखाने के लिए ये अपने नाम बदल लेते थे, यहां तक कि धार्मिक दुपट्टे और कलावे भी पहन लेते थे ताकि किसी को इन पर शक न हो।

# नोएडा भाजपा महानगर अध्यक्ष को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती

**नोएडा।** नोएडा के सेक्टर 116 में स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय पर विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) का काम कर रहे नोएडा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान को मंगलवार शाम चार बजे के करीब दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अचेत देखकर भाजपा नेता अमित त्यागी ने कार से सेक्टर 50 स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने स्टंट डालकर उनकी जान बचाई। बुधवार सुबह से ही उनको देखने के लिए लोग अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही विधायक पंकज सिंह को मिली उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात की। फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है। भारतीय जनता पार्टी नेता अमित त्यागी ने बताया कि मंगलवार को शाम चार बजे के करीब भाजपा कार्यालय में वह महानगर अध्यक्ष महेश चौहान और अन्य लोगों के साथ एसआईआर का कार्य कर रहे थे। अचानक महेश चौहान को सीने में तेज दर्द उठा और वह बोलते-बोलते अचेत हो गए। यह देख उन्होंने बिना समय गवांए भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष को कार में बैठाया और एक दवाई खिलाकर अस्पताल ले गए। रास्ते में उन्होंने नोएडा विधायक पंकज सिंह को घटना की सूचना दी।

विधायक के फोन पर विशेषज्ञों की टीम अलर्ट हुई। सात मिनट में वह भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष को मेदांता अस्पताल लेकर पहुंचे और 12 मिनट में टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद विधायक पंकज सिंह भी अस्पताल आ गए। उन्होंने महानगर अध्यक्ष के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

# आयकर विभाग से रिटायर्ड कमिश्नर के फार्म हाउस पर कब्जे का प्रयास, मुकदमा दर्ज

**नोएडा।** थाना एक्सप्रेसवे इलाके में आयकर विभाग से रिटायर्ड कमिश्नर के फार्म हाउस पर दो लोगों ने तोड़फोड़ कर कब्जा करने का प्रयास किया है। इस दौरान आरोपित मौके से कुछ सामान भी उठा ले गए। पीड़ित रिटायर्ड कमिश्नर के दामाद की शिकायत पर थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना एक्सप्रेसवे के प्रभारी विपिन कुमार ने बुधवार को बताया कि बीती रात मंगलवार को मोहम्मद सैफ ने थाने में तहरीर दी कि सेक्टर 35 में रहने वाले उनके ससुर जमील अहमद रिटायर्ड आयकर कमिश्नर हैं। ससुर का ग्राम नगला नगली डूब क्षेत्र में एक फार्म हाउस है। उन्होंने यह फार्म हाउस सन् 2013 में वीरेंद्र कुमार यादव से खरीदा था और उनके पास इसका कब्जा है। फार्म हाउस को तारकशी करवाकर एक कमरा बनवा बना है और उसकी देख रेख के लिए मुनेंद्र नामक व्यक्ति को रखा गया है। मंगलवार को केयरटेकर मुनेंद्र फार्म हाउस पर मौजूद था, तभी वहां पर ग्राम बाजितपुर के रहने वाले पवन और मोनू पुत्र रोहतास आए। दोनों ने फार्म हाउस में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जब केयरटेकर ने मना किया तो आरोपितों ने उसे गालियां देते हुए मारपीट की।

इस दौरान आरोपितों ने धमकी देते हुए कहा कि यह जमीन हमारी है, तुम यहां से भाग जाओ। केयरटेकर ने इसकी सूचना मालिक को दी। पीड़ित के अनुसार, जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों लोगों ने साइट पर लगे हुए 35 खंभे और 600 मीटर कटीले तार वहां से उखाड़ दिए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड निदेशक के साथ साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

**नोएडा।** थाना सेक्टर 113 में स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक ने आईजीएल गैस का बिल जमा कराने के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा एक लाख 97 हजार 245 रुपये उनके खाते से निकाले जाने की तहरीर दी है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। थाना सेक्टर 113 के निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बुधवार को बताया कि बीती रात मंगलवार को सेक्टर 76 स्थित आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजेश्वर कुमार वत्स ने थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया गया कि उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि आईजीएल गैस कंपनी का पेमेंट बकाया है। तुरंत भर दीजिए नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। उन्होंने कॉल करने वाली की बात पर विश्वास किया। पीड़ित के अनुसार झांसे में लेकर जालसाज ने उनसे उनके डेबिट कार्ड की डिटेल ली तथा उनके खाते से धोखाधड़ी कर एक लाख 97 हजार 245 रुपये निकाल लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

# पेंशनर दिवस: पेंशनरों का किया सम्मान, समस्याओं के समाधान का आश्वासन

**नोएडा।** जनपद गौतमबुद्ध नगर के पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन सभागार में पेंशनर दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी ने की। इस मौके पर उन्होंने जनपद के वरिष्ठ पेंशनर्स आरएन चौधरी आयु 92 वर्ष, राजेश पांडेय आयु 87 वर्ष, कृष्णपाल सिंह आयु 97 वर्ष, महेश प्रसाद आयु 93 वर्ष तथा हरीश चन्द्र अग्रवाल आयु 87 वर्ष को फूल माला एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के वरिष्ठ पेंशनर्स से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशनर्स से संबंधित सभी प्रकरणों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी पेंशनर्स से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करते हुए उनके द्वारा शासकीय सेवा में दिए गए अमूल्य योगदान की प्रशंसा की तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। उन्होंने आश्वस्त किया कि पेंशनर दिवस में प्रस्तुत सभी समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी शिखा गुप्ता द्वारा पेंशन दिवस के महत्व एवं उसके उद्देश्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पेंशन दिवस का आयोजन शासकीय सेवाओं में वर्षों तक निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से अपनी सेवाएं देने वाले पेंशनरों के सम्मान तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी पेंशनर्स ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शासकीय सेवा में समर्पित किया है और उनके अनुभव व योगदान शासन के लिए अमूल्य हैं।

उन्होंने कहा कि पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि शासकीय सेवाओं में दिए गए उनके दीर्घकालीन योगदान का सम्मान है। पेंशनर दिवस के दौरान पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराज सिंह चैहान एवं अन्य पेंशनर्स द्वारा इनकम टैक्स, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान, आर्म्स लाइसेंस नवीनीकरण, पेंशन निर्धारण, शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों सहित अन्य विभिन्न समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इन सभी विषयों पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, पेंशनर्स द्वारा आठवें वेतन आयोग में पूर्व पेंशनर्स को भी सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कोषाधिकारी शिखा गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश, एसीएमओ डॉ हरिमोहन गर्ग, वरिष्ठ लेखाकार शरद रस्तोगी, राजीव त्यागी, शिल्पी शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।

## बड़ा हादसा टला: तेज रफ्तार कैब नाले में गिरी, चालक सुरक्षित

**नोएडा।** फेस-दो थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। एनएसईजेड चौकी के सामने तेज रफ्तार से जा रही एक कैब अनियंत्रित होकर सेफ्टी वॉल तोड़ते हुए नाले में गिर गई। गनीमत रही कि कैब चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। घटना के समय चालक आलोक कैब लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था। अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। कैब के नाले में गिरते ही तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास मौजूद लोग और राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए।घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने चालक आलोक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फेस-दो थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने क्रेन की मदद से कैब को नाले से बाहर निकलवाया और वाहन मालिक दीपक को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं, विशेषकर शहरी इलाकों और मोड़ों पर सतर्कता बरतें।

## नववर्ष, क्रिसमस सहित किसी समारोह में शराब परोसने के लिए ऑकेजनल लाइसेंस अनिवार्य

**नोएडा।** नववर्ष, क्रिसमस पार्टी और अन्य प्रकार के समारोह में मदिरा परोसने के लिए आयोजकों को अब लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है। यह जानकारी बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने दी है।जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि जिले के समस्त बार, बैंक्विट हॉल प्रबंधन, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट और होटल के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है। किसी भी तरह की पार्टी में मदिरा परोसने के लिए अकेजनल बार लाइसेंस लेना होगा।

नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदक आबकारी विभाग की बेवसाइट upexciseportal.in के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विस में अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) पर पंजीकरण कराकर एवं ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। बिना लाइसेंस के किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय।

यदि कोई भी होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब, विभिन्न आरडब्ल्यूए एवं मैरिज हॉल अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुये पाया जाता है। तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

# वंडरलैंड फूड्स नामक कंपनी को 30 हजार वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि का किया आवंटन

## कंपनी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए करेगी 240 करोड़ की निवेश

**नोएडा।** यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-8डी में 240 करोड़ के निवेश से एक ग्रीनफील्ड नट्स एवं ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। परियोजना को मूर्त रूप देने के मकसद से वंडरलैंड फूड्स नामक कंपनी को 30 हजार वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि का का आवंटन किया गया है।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वंडरलैंड फूड्स भारत के प्रीमियम नट्स एवं ड्राई फ्रूट्स उद्योग में अग्रणी नामों में से एक है। स्वस्थ आहार को सरल, सुलभ और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से स्थापित इस ब्रांड ने गुणवत्ता, प्रामाणिकता और नवाचार के बल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि अपने व्यवसाय के विस्तार की दिशा में वंडरलैंड फूड्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में लगभग 240 करोड़ के निवेश से एक ग्रीनफील्ड नट्स एवं ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित परियोजना में आंशिक वित्तपोषण के लिए आशा वेंचर्स फंड-1 तथा ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पीएलसी (यूनाइटेड किंगडम सरकार का उपक्रम) द्वारा कंपनी में 140 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राकेश कुमार सिंह ने सेक्टर 8डी में परियोजना के लिए 30,000 वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि का आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) कंपनी के चेयरमैन राकेश कुमार गुप्ता को प्रदान किया। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) शैलेंद्र भाटिया और राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 24 महीनों के भीतर परियोजना में उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।

वहीं कंपनी के संस्थापक राकेश कुमार गुप्ता के अनुसार, यह परियोजना समाज के कमजोर वर्ग से आने वाली 750 से अधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। परियोजना के पूर्ण रूप से परिचालन में आने पर इससे प्रतिवर्ष 800 करोड़ से अधिक का राजस्व सृजित होने की संभावना है।

## संपादकीय

# मोदी का 'नबीन' प्रयोग

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नितिन नबीन की नियुक्ति से राजनीतिक पंडितों और पार्टी के अधिकांश नेताओं को एक बार फिर चौंकाया है। बेशक पार्टी संसदीय बोर्ड का हवाला देती रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व और संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री मोदी ही तय करते हैं। कुछ मामलों में गृहमंत्री अमित शाह की सलाह भी ली जाती है। आरएसएस की सहमति भी अनिवार्य है, लेकिन बुनियादी तौर पर चयन मोदी ही करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा, इस नियुक्ति की घोषणा से मात्र दो दिन पहले, संसदीय बोर्ड में की गई थी, लेकिन उस दौरान कोई नाम सामने नहीं था। संसदीय बोर्ड के अधिकांश सदस्यों की राय थी कि पार्टी का भावी अध्यक्ष अपेक्षाकृत युवा हो, सवर्ण जाति का हो और हिंदी पट्टी के राज्य से हो। इन्हीं आधारों पर बिहार के 5वीं बार विधायक एवं मंत्री नितिन नबीन का चयन किया गया। वैसे भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक-दो अपवाद को छोड़ कर, सवर्ण जाति के ही रहे हैं। बेशक राज्यों में पिछड़े और दलित समुदाय के नेताओं को भी नेतृत्व सौंपा जाता रहा है। नितिन नबीन सवर्ण उपजाति-कायस्थ समुदाय-के नेता हैं और 45 साल उम्र है, लिहाजा वह भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कुछ समय बाद वह जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बेशक नितिन नबीन भाजयुमो में अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर चुके हैं, कुछ राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारी भी रहे हैं, लिहाजा संगठन की आत्मा और अपेक्षाओं को वह बखूबी जानते हैं। जब नड्डा पार्टी अध्यक्ष बने थे, तब उनकी उम्र 52 साल थी। अमित शाह 49 साल के थे। राजनाथ सिंह भी 52-53 साल के रहे होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की आयु भी 55-58 साल की रही होगी, जब वे पहली बार भाजपा अध्यक्ष बने थे, लिहाजा उम्र शीर्ष नेतृत्व का कोई मानदंड नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह 'नबीन' प्रयोग चुनौतीपूर्ण जरूर है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर मोहन चरण माझी, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, बिप्लव देब, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी आदि को विराजमान कर भाजपा की नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा था। इन्हीं नेताओं की तरह नबीन भी भाजपा की चौथी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। अलबत्ता उनकी पहचान कभी 'राष्ट्रीय' नहीं रही। बहरहाल अब नितिन नबीन भी उसी श्रृंखला की नई कड़ी बन गए हैं, जिसे अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा तक ने स्थापित किया और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सम्मान दिलाया। उस वर्चस्व, ओहदे और गरिमा को बरकरार रखना भी नितिन नबीन की चुनौती है।

*अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज देने पर सहमत हो गया, लेकिन उसने कड़ी शर्तें लगाई। इनमें संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन, व्यापार उदारीकरण और मुद्रा का डीवैल्युएशन शामिल था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह की लीडरशिप में ऐतिहासिक सुधार हुए। भारत ने लाइसेंस राज को खत्म किया, आयात शुल्क कम किए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए दरवाजे खोले और साथ ही खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलाया। आइये रुपए की इस गिरावट के चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करें। रुपया और डॉलर का रेट तय होने का भी एक बाजार है, जिसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। यहां बैंक, बड़ी कंपनियां और निवेशक डॉलर खरीदते-बेचते हैं। जब डॉलर की मांग ज्यादा होती है और बाजार में डॉलर कम मिलते हैं, तो डॉलर महंगा और रुपया सस्ता हो जाता है। भारत ज्यादा आयात करे और निर्यात कम हो, तो हमें डॉलर में ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, मांग बढ़ती है और रुपया टूटता है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची हों, तो विदेशी निवेशक वहां पैसा लगा देते हैं, भारत से डॉलर निकलते हैं और रुपया कमजोर होता है।*

# प्रदूषण अब राष्ट्रीय समस्या

**- मनोज कुमार मिश्र**



प्रदूषण अब केवल दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की समस्या नहीं है, यह देश के करीब साठ फीसदी इलाके की समस्या बन गया है। दिल्ली में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 पार कर चुका है और प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले मानक-ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (गैप)-चार को पूरे एनसीआर में बार-बार लागू किया जा रहा है। इसे प्रदूषण के मामले में आपात स्थिति माना जाता है। निर्माण कार्य और बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के अलावा लोगों को घरों से बाहर निकलने को एक तरह से सीमित कर दिया जाता है। खासकर बच्चे और साठ साल से ज्यादा उम्र वालों पर इस हालात का ज्यादा असर होता है। सांस की बीमारियों के अलावा अनेक भयावह बीमारियों का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण माना जाता है।

अब मुंबई जैसे समुद्र के किनारे बसे महानगर में भी एक्यूआई 150 पार करने पर गैप लागू कर दिया गया है। एक्यूआई का 100 पार हो जाना ही खतरनाक माना जाता है। मुंबई में प्रदूषण का बड़ा कारण बेहिसाब हो रहे निर्माण कार्य और वाहनों की भीड़ माना जा रहा है। दक्षिण भारत के बड़े शहरों के अलावा पुणे, रांची और पहाड़ों पर बसे शहरों के साथ पूरा देश प्रदूषण के भयावह संकट का सामना कर रहा है। यह संकट जितना बड़ा है, समाधान उससे ज्यादा कठिन हो रहा है। अदालतों की फटकार और वैज्ञानिकों के तमाम सुझाव इस संकट को कम नहीं कर पा रहे हैं। अब तो प्रदूषण एक तरह से स्थाई समस्या बन गया है। जाड़ों की सुबह आसमान कोहरे से ढंका रहे, अब यह असंभव लगने लगा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के इलाके में सवेरे-शाम ही नहीं दिन-रात के ज्यादातर समय प्रदूषण से ढंका रहने लगा है।

सरकारें चाहे जो दावा करें लेकिन हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिनके बूते में है या जिनके पास विकल्प है, वे इस इलाके से पलायन कर रहे हैं या जाड़े के समय किसी अन्य स्थान पर जा रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोग जान जोखिम में रख कर दिल्ली-एनसीआर में जीने को मजबूर हैं। इस भीषण प्रदूषण के कारण अनेक लोगों की जान चली गई और बड़ी तादाद में लोग विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स इसे मेडिकल इमरजेंसी तक मान चुका है। तभी बार-बार प्रदूषण से लोगों की जान बचाने के लिए गैप-4 लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में यह कई साल पहले साबित हो चुका है कि केवल आधे कारों को हर रोज सड़क पर आने से रोकने से वायु प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं आने वाली है दूसरे, सरकारी कुव्यवस्था को झेल रहे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस बार इस हालत में भी नहीं है कि दिल्ली सरकार इस बार निजी कारों का सम-विषम का फिर से प्रयोग कर सके। दिल्ली की लाइफ लाइन बनी मेट्रो रेल को सामाजिक दूरी के हिसाब से तमाम एहतियात के साथ चलाया जा रहा है। उसे पहले की तरह हर रोज 60 लाख से ज्यादा यात्रियों को यात्रा कराने की क्षमता बनाने अभी समय लगेगा। इतना ही नहीं मेट्रो भी अब कम आय वालों के बूते से बाहर होती जा रही है। दिल्ली की बेहिसाब आबादी को प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। पहले अवैध औद्यौगिक इलाके, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रक-बस आदि के चलते भी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का कारण माना जाता था। वैसे अभी भी अवैध उद्योग हैं, भले उनकी संख्या कम हुई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी नए उत्पादन ईकाई (मैनिफ्कैचरिंग यूनिट) को लाईसेंस देने पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है।

देश के कई शहरों और राज्यों में प्रदूषण की यही हालत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 60 फीसदी आबादी प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली और एनसीआर में रह रहे लोग प्रदूषण नियंत्रण करने की विभिन्न योजनाओं और उपायों से लगातार परिचित होते जा रहे हैं। इनकी फेहरिस्त देखें तो कभी डीजल के वाहनों पर पाबंदी, कभी निर्माण कार्यों पर रोक, कभी स्कूल बंद तो तभी दफ्तरों में घर से काम करने के आदेश से लेकर कोरोना की तरह बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह सरकार दे रही है। किसानों के पराली (फसलों के अवशेष) जलाने पर सजा के प्रावधान से लेकर कारों को सम-विषम चलाने का प्रयोग दिल्ली देख चुकी है। बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार दो साल कोरोना में हजारों अपनों को खोने वाले अब और किसी महामारी को झेलने की हालत में नहीं हैं। कोरोना प्राकृतिक आपदा थी जबकि प्रदूषण पूरी तरह मानव निर्मित, जो हमारी गलतियों और सरकारों की लापरवाही या गलत नीतियों के चलते समाज को भुगतनी पड़ रही है। वास्तव में प्रदूषण संकट से देश घिरता जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद केन्द्र सरकार के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में दिल्ली के प्रदूषण का समाधान निकालने का वायदा किया था। अभी तक उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सार्वजनिक रूप से अब तक प्रदूषण कम न करने के लिए माफी मांगी है। उनका कहना था कि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन कुछ महीने में सबकुछ ठीक नहीं हो सकता है। दिल्ली सरकार समेत एनसीआर में आने वाले दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी आदेश जारी कर प्रदूषण से फौरी राहत दिलाने के प्रयास किए लेकिन इससे न तो वाहनों का सड़क पर आना कम हुआ और न ही प्रदूषण में कोई कमी आती दिख रही है।

पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा के बजाए आम जन के जीवन को बचाने का मुद्दा बनाया जाए। चालू समाधान नहीं स्थायी समाधान तलाशे जाने की जरूरत है। देरी खतरनाक साबित होती जा रही है। स्थिति इतनी विकट है कि इसका समाधान अकेले दिल्ली सरकार के बूते नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों और दिल्ली की नगर निगमों के साथ-साथ दूसरी सरकारी एजेंसियों को साथ लेकर जनता की सक्रिय भागीदारी से इसका समाधान निकाला जा सकता। यह केवल कहने से नहीं होगा, इसे जन भागीदारी से सफल करवाना होगा।

# संसद का अवरुद्ध स्वर और लोकतंत्र की कसौटी

**-डॉ. प्रियंका सौरभ-**

भारतीय संसद लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। यही वह मंच है जहाँ जनता की विविध आकांक्षाएँ, असहमतियाँ और अपेक्षाएँ बहस के माध्यम से नीति और कानून का रूप लेती हैं। किंतु हाल के वर्षों में संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित होने, प्रश्नकाल के स्थगित रहने, विधेयकों के बिना पर्याप्त चर्चा पारित होने और सदन के समय से पहले स्थगन ने इसकी गरिमा और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। संसद, जो संवाद और सहमति का प्रतीक होनी चाहिए थी, वह अनेक अवसरों पर टकराव और अवरोध का अखाड़ा बनती दिखी है। यह स्थिति केवल संसदीय परंपराओं का क्षरण नहीं, बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की जड़ों के कमजोर होने का संकेत भी है।

संसद में व्यवधान कोई नया विषय नहीं है। विरोध, असहमति और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में अनिवार्य है। किंतु जब विरोध का प्रमुख औजार निरंतर हंगामा, नारेबाजी और कार्यवाही ठप करना बन जाए, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रही है। बार-बार स्थगित होने वाली कार्यवाही का सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है, क्योंकि संसद का हर खोया हुआ घंटा नीतिगत विमर्श, जनहित के मुद्दों और विधायी समीक्षा से चूक का प्रतीक बन जाता है। यह स्थिति कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाती है और विधायिका की निगरानी भूमिका को कमजोर करती है।

लोकतांत्रिक शासन में संसद केवल कानून पारित करने की मशीन नहीं होती, बल्कि वह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने, नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करने और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ को सामने लाने का मंच भी होती है। जब संसद बाधित होती है, तब कार्यपालिका पर सवाल पूछने के अवसर कम होते हैं, अध्यादेशों और 'गिलोटिन' जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से विधायी निगरानी कमजोर पड़ती है और निर्णय कुछ सीमित हाथों में केंद्रित होने लगते हैं। इस संदर्भ में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता केवल तकनीकी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है।

संसदीय समितियों की भूमिका इस बहस में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में संसदीय समितियाँ सदन के बाहर अपेक्षाकृत शांत वातावरण में विधेयकों की बारीकी से जांच करने, विशेषज्ञों और हितधारकों की राय लेने तथा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर व्यावहारिक सुझाव देने का मंच प्रदान करती हैं। जब अधिकाधिक विधेयकों को बिना समिति जांच के पारित किया जाता है, तो कानून निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। संस्थागत सुधार के रूप में सभी प्रमुख विधेयकों को अनिवार्य रूप से समितियों को भेजना न केवल विधायी प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि संसद के भीतर होने वाले टकराव को भी कम कर सकता है, क्योंकि असहमति का समाधान बहस और प्रमाण के माध्यम से बाहर संभव होगा।

प्रश्नकाल को संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। यही वह समय होता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे-सीधे मंत्रियों से जनता से जुड़े सवाल पूछते हैं और सरकार को अपने निर्णयों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। प्रश्नकाल का बार-बार बाधित होना या औपचारिकता में सिमट जाना कार्यपालिका की जवाबदेही को कमजोर करता है। संस्थागत सुधार के तहत प्रश्नकाल की सुरक्षा और उसकी अनिवार्यता तय करना आवश्यक है, ताकि किसी भी परिस्थिति में इसे स्थगित न किया जाए। इससे सरकार और विपक्ष दोनों को संवाद के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए आचार-संहिता और दंडात्मक प्रावधान भी आवश्यक हैं। वर्तमान में नियम तो मौजूद हैं, किंतु उनका निष्पक्ष और सुसंगत क्रियान्वयन अक्सर विवादों में घिर जाता है। यदि सांसदों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और सर्वसम्मति से तय आचार-संहिता हो तथा उसके उल्लंघन पर समान रूप से कार्रवाई हो, तो अव्यवस्थित आचरण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। यह सुधार केवल दंड देने का नहीं, बल्कि संसदीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन सकता है।

संसद के कार्यदिवसों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण संस्थागत मुद्दा है। भारत की संसद कई विकसित लोकतंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम दिन बैठती है। सीमित सत्रों में भारी विधायी एजेंडा न केवल सांसदों पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि सार्थक बहस की संभावना को भी कम करता है। न्यूनतम निश्चित बैठक दिनों वाला कैलेंडर तय करना और उसका सख्ती से पालन करना विधायी गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। अधिक बैठकों का अर्थ केवल अधिक कानून नहीं, बल्कि अधिक संवाद, अधिक प्रश्न और अधिक जवाबदेही है।

हालाँकि, इन संस्थागत सुधारों की राह आसान नहीं है। राजनीतिक दल अक्सर संसद के भीतर व्यवधान को एक वैध राजनीतिक हथियार मानते हैं। विपक्ष को यह आशंका रहती है कि सुधारों के नाम पर उसके विरोध के अधिकार को सीमित किया जाएगा, जबकि सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है कि वह संस्थागत नियमों का उपयोग असहमति को दबाने के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त, स्पीकर या सभापति की निष्पक्षता पर उठने वाले सवाल भी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगे, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी विवाद का कारण बन जाती है।

कार्यपालिका का बढ़ता प्रभुत्व भी एक गंभीर चिंता है। अध्यादेशों का बढ़ता प्रयोग, धन विधेयकों के दुरुपयोग और समयाभाव के नाम पर बहस सीमित करने की प्रवृत्ति संसद की भूमिका को कमजोर करती है। ऐसे में केवल नियम बदलना पर्याप्त नहीं होगा; सत्ता और विपक्ष दोनों को संसदीय मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी। संस्थागत सुधार तभी सार्थक होंगे जब उन्हें राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन प्राप्त हो।

अंततः संसद की मजबूती किसी एक सुधार या नियम से सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें संस्थाएँ, परंपराएँ और राजनीतिक आचरण तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। संसद को फिर से बहस, सहमति और उत्तरदायित्व का मंच बनाने के लिए आवश्यक है कि विरोध संवाद में बदले, असहमति अवरोध में नहीं, और शक्ति संतुलन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बना रहे। तभी भारतीय संसदीय लोकतंत्र न केवल व्यवधानों से उबर पाएगा, बल्कि एक जीवंत, प्रतिनिधिक और जवाबदेह संस्था के रूप में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित कर सकेगा।

# वास्तु शास्त्र में तांबा का चमत्कारी प्रभाव, जाने कैसे करें इस्तमाल

वैज्ञानिक तौर पर तांबा शरीर के लिए उपयोगी माना गया है, लेकिन आज हम आपको बता रहें है कैसे ज्योतिषशास्त्र के अनुसार तांबा आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है। तांबे की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इसे धारण किया जा सकता है। आइये जानते है तांबा पहनने के क्या फायदे होते है....

-अगर आपके घर में वास्तुदोष है जिसके कारण आपके और आपके परिवार के सदस्यों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वास्तु के अनुसार अपने घर में एक चौकोर तांबे का टुकड़ा रखें। ऐसा करने से आपका घर वास्तुदोष से मुक्त होगा।

धर्मकर्म

-अगर आपने घर बनवाते समय वास्तु के नियमों को ध्यान में नहीं रखा है और आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं है तो अपने दरवाजे के वास्तुदोष को दूर करने के लिए दरवाजे पर तांबे के सिक्के लटका दें। ये सिक्के आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होने देंगे।

-अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में दोष है तो आप इस दिशा के दोष से छुटकारा पाने के लिए ठोस तांबे का पिरामिड घर में रखें। इसे घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

-छोटे बच्चे को अगर बार-बार नजर लग जाती है तो आप अपने बच्चे को एक तांबे के सिक्के में छेद करके उसे काले धागे में पिरोकर बच्चे को पहनाएं। ऐसा करने से आपका बच्चा किसी की बुरी नजर से सुरक्षित रहेगा।

-तांबे की अंगूठी पहने से व्यक्ति के सूर्य दोष दूर होते हैं। इसलिए अगर कमजोर सूर्य के कारण जीवन में परेशानियां आप कम नहीं कर पा रहे तो ऐसे में यह अंगूठी पहनें। बहुत जल्द आपको इसका असर दिखेगा, आपको मान-सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी।

-तांबे की अंगूठी गुस्सा नियंत्रण करने में कारगर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शांत प्रकृति का है और गर्मी दूर करता है। इसलिए व्यक्ति के मानसिक स्थिति को संतुलित कर गुस्सा शांत करता है।

## आज का इतिहास

1271 – मंगोल शासक कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई।

1398 - तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया।

1642 - समुद्री खोजी नाविक तस्मान आज के दिन न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा, उसी के नाम पर न्यूजीलैंड के समीपवर्ती समुद्र को तस्मानिया समुद्र कहा जाता है।

1787 - अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी तीसरा राज्य बना।

1833 - रूस का राष्ट्रीय गान 'गॉड सेव द जार' पहली बार गाया गया।

1865 - अमेरिका के संविधान में 13वां संशोधन अपनाया गया, जिससे देश में दास प्रथा समाप्त हो गई।

1878 - अल-थानी परिवार कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना।

1956 - जापान ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सदस्यता ग्रहण की और वह उसका 80वां सदस्य बना।

1960 - नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ।

1961 - भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, जिसे 'ऑपरेशन विजय' नाम दिया गया।

1969 - इंगलैंड में मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी गई।

1973 - इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना।

1989 - सचिन ने अपना पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।

1990 - संयुक्त राष्ट्र ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन अपनाया, जिससे 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा।

1995 - अज्ञात विमान ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया।

1997 - भारत और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि सम्पन्न।

1999 - श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग पर हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 घायल।

2000 - फ्रांस के जाने-माने अभिनेता करार्ड ब्लेन का निधन।

2002 - हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सिपिदान और लिगितान द्वीपों पर नियंत्रण के मामले में मलेशिया के अधिकार की पुष्टि की।

# भाजपा में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के निहितार्थ

**-अनिल जैन-**

भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बिहार के एक नेता नितिन नवीन की जिस तरह से नियुक्ति हुई है, उससे पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश जेपी नड्डा की यह बात एक बार फिर सच साबित हुई है कि 'भाजपा अब हर मामले' में सक्षम और आत्मनिर्भर हो चुकी है और उसे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद या उसके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रह गयी है।' जेपी नड्डा ने यह बात पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान साल 20 मई, 2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए इंटरव्यू में कही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में संघ हमेशा की तरह भाजपा के लिए सक्रिय था, फिर भी भाजपा की '400 पार' की हसरत पूरी नहीं हो सकी थी। वह बहुमत से दूर रही थी और उसे सरकार बनाने के लिए करीब डेढ दर्जन छोटे-बड़े क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ा।

लोकसभा चुनाव के बाद चार राज्यों-महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीते। ऐसा नहीं है कि इन चुनावों में संघ ने भाजपा की मदद नहीं की, लेकिन भाजपा की जीत में संघ से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वह हिकमत अमली प्रभावी रही, जिसमें चुनाव आयोग, प्रशासन तंत्र, मीडिया और कुछ हद तक न्यायपालिका की भूमिका का भी शुमार रहा। इन चार राज्यों में मिली जीत से जेपी नड्डा की बात सही साबित हुई। सब जानते हैं कि नड्डा पार्टी अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन सर्वशक्तिमान अध्यक्ष नहीं। पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से वे वही कहते और करते हैं, जैसा उन्हें निर्देशित किया जाता है। इसलिए यह आसानी से समझा जा सकता है कि 'अब संघ की जरूरत नहीं है और भाजपा आत्मनिर्भर हो चुकी है'- जैसी इतनी बड़ी बात उन्होंने किसके इशारे पर कही होगी। दरअसल भाजपा के 45 साल के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद सिर्फ अमित शाह ही ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। उनके अलावा अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी में से कोई वाजपेयी-आडवाणी का तो कोई संघ का रबर स्टैंप ही रहा। हालांकि वाजपेयी और आडवाणी के फैसलों पर भी संघ की कम-ज्यादा छाप हुआ करती थी। संघ की छाप कुछ समय अमित शाह के फैसलों पर भी रही लेकिन वह धीरे-धीरे खत्म होती गई। पांच साल तक पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद जब अमित शाह केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उनकी जगह जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाए गए, जो अभी बने हुए हैं।

वैसे जेपी नड्डा का कार्यकाल लगभग दो साल पहले खत्म हो चुका है। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं लेकिन उनकी जगह नया अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया जा सका है क्योंकि संघ और मोदी-शाह के बीच नए अध्यक्ष को लेकर किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। मोदी-शाह अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं जो नड्डा की तरह उनका फरमानबरदार रहे, जबकि संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष मोदी की छाया से मुक्त होकर उसके निर्देशन में काम करे।

बहरहाल इसी खींचतान के चलते बिहार के युवा नेता नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह फैसला शुद्ध रूप से मोदी-शाह का है, जिसे पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में संसदीय बोर्ड का फैसला बताया है। यह फैसला लेने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक कब और कहां हुई, इसका कोई ज़िक्र उनकी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है। इस बारे में भाजपा के नेताओं या प्रवक्ताओं से भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। टीवी चैनलों पर नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का अनर्गल गुणगान हो रहा है। जिस व्यक्ति की बिहार में ही कोई ठीक-ठाक राजनीतिक पहचान नहीं है, उसे कुशल संगठक और ऊर्जावान नेता बताया जा रहा है। पहले कभी किसी ने नहीं कहा लेकिन अब कहा जा रहा है कि बतौर प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। सवाल यह भी है कि अगर नितिन नवीन इतने ही प्रभावशाली नेता हैं तो उन्हें इससे पहले बिहार में ही भाजपा का अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया गया? बिहार सरकार में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन नितिन नवीन को उप मुख्यमंत्री बनाने लायक भी क्यों नहीं समझा गया?

टीवी चैनलों पर नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को 'मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक' बताते हुए कहा जा रहा है कि इससे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और बंगाल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में इस समुदाय का काफी प्रभाव है। यह समुदाय बंगाल की राजनीति में पहले बहुत लंबे समय तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का समर्थक रहा और पिछले डेढ़ दशक से मोटे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन बंगाल के कायस्थ समुदाय को भाजपा की ओर आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि बंगाल के कायस्थों का उत्तर भारत के कायस्थों से सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर कोई मेल नहीं है।

बहरहाल गौरतलब यह भी है कि भाजपा के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता पार्टी में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है, जिसके मुताबिक खुद जेपी नड्डा भी 2019 में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। नड्डा से पहले एक बार 2001 में महज 10 दिन के लिए जना कृष्णमूर्ति कार्यवाहक बनाए गए थे। उस समय तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते पकड़े गए थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया था और उनके स्थान पर कृष्णमूर्ति को पहले कार्यवाहक अध्यक्ष और बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। इस समय तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जेपी नड्डा अध्यक्ष बने हुए हैं, फिर भी उनके साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। जाहिर है कि मोदी-शाह ने इस फैसले के जरिए न सिर्फ संघ को उसकी हैसियत बताई है, बल्कि मीडिया में अपने को भाजपा की राजनीति का जानकार समझने वाले उन लोगों को भी हास्यास्पद बना दिया है जो पिछले कई महीनों भाजपा अध्यक्ष पद के लिए दर्जन भर से ज्यादा नामों को दावेदार बता रहे थे।

मोदी-शाह ने इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनने के मामले में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने इन प्रदेशों में संघ की पसंद को दरकिनार करते हुए अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बनाए। यह सही है कि इन चारों राज्यों में जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन सभी का संघ से जुड़ाव है लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए वे संघ नेतृत्व की पसंद कतई नहीं हैं। दरअसल नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने अपनी हनक और मीडिया प्रबंधन के जरिये अपने कद को पार्टी से भी बड़ा बना लिया है। अब उन्हें पार्टी की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे पार्टी की जरूरत बन गए हैं। अलबत्ता वे सरकार के स्तर पर संघ के एजेंडा के मुताबिक काम करने में कोई कोताही नहीं करते हैं। संघ को जहां जरूरत होती है, वहां सरकारी संसाधनों से भरपूर मदद भी मुहैया कराई जाती है, मगर सत्ता और संगठन में संघ की दखलंदाजी से उन्हें गुरेज़ है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व ए-152, सैक्टर 63, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से प्रकाशित।
संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई.- UPHIN/2023/84499
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

# साल 2026 के अंत तक देशभर में टोल भुगतान की नई व्यवस्था: नितिन गडकरी

**नई दिल्ली।** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में कहा कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) वर्ष 2026 के अंत तक देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू कर दी जाएगी। इसके लागू होने के बाद टोल नाकों पर वाहन 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके गुजर सकेंगे।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान झारखंड से भाजपा सांसद आदित्य प्रसाद के प्रश्न का उत्तर देते हुए गडकरी ने बताया कि एमएलएफएफ प्रणाली में टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। कैमरों से वाहन नंबर की पहचान होगी, उपग्रह के माध्यम से जानकारी केंद्रीकृत प्रणाली तक पहुंचेगी और संबंधित बैंक खाते से स्वतः टोल कट जाएगा। इससे ईंधन की बचत होगी और यातायात सुगम होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से करीब 1,500 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की आय में कम से कम छह हजार करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। गडकरी ने बताया कि कुछ स्थानों पर यह प्रणाली पहले ही लागू की जा चुकी है।

अब तक 10 ठेके आवंटित किए जा चुके हैं और 10 ठेकों की प्रक्रिया जारी है। अगले साल के अंत तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर हाल में हुई दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हादसे के एक घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंचना दुखद है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 100-150 अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इनके संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी और शर्त यह होगी कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.80 लाख लोगों की मौत होती है। मृतकों में 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के 66 प्रतिशत लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार तथा कानून सख्त किए जाने के बावजूद मानवीय व्यवहार जैसे वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, हेलमेट न पहनना और लेन नियमों का उल्लंघन बड़ी समस्या बना हुआ है।

गडकरी ने बताया कि समय पर इलाज न मिलने से 50 हजार मौतें होती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने दो योजनाएं शुरू की हैं। पहली, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 'राहवीर' घोषित कर 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी, घायल को जिस अस्पताल में ले जाया जाएगा, वहां कम से कम सात दिन तक डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज खर्च एनएचएआई फंड से वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से एम्बुलेंस सेवाओं के लिए अलग-अलग आपातकालीन नंबरों की जगह एकल नंबर व्यवस्था लागू करने को कहा गया है, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित हो सके।

## ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा: वैष्णव

**नई दिल्ली।** रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को बताया कि ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा। वैष्णव ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह बात कही। रेड्डी ने जानना चाहा था कि क्या रेलवे, हवाई अड्डों पर अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप ट्रेन यात्रियों के लिए सामान संबंधी नियम लागू करेगा।

वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में, यात्रियों द्वारा डिब्बों के अंदर अपने साथ सामान ले जाने की श्रेणीवार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। रेल मंत्री द्वारा लिखित उत्तर में साझा की गई जानकारी के अनुसार, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलोग्राम वजन तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है और शुल्क देकर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है। वहीं, स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए 40 किग्रा सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है और अधिकतम सीमा 80 किग्रा है। मंत्री द्वारा सदन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 'एसी थ्री टियर' या 'चेयर कार' में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किग्रा तक निशुल्क सामान ले जाने की अनुमति है, जो इसकी अधिकतम सीमा भी है।

वहीं, प्रथम श्रेणी और 'एसी टू टियर' के यात्रियों को 50 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 किग्रा है। एसी प्रथम श्रेणी के यात्री 70 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जा सकते हैं, जबकि शुल्क देकर 150 किग्रा तक सामान ले जाया जा सकता है। वैष्णव के अनुसार, 100 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेमी चौड़े और 25 सेमी ऊंचाई तक के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से को व्यक्तिगत सामान के रूप में यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि ट्रंक, सूटकेस और बक्से, जिनका बाहरी माप किसी भी रूप में अधिक है, तो ऐसी वस्तुओं को यात्रियों के डिब्बों में नहीं, बल्कि ब्रेकवैन (एसएलआर)/पार्सल वैन में बुक करके ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि निजी सामान के रूप में वाणज्यिक वस्तुओं की डिब्बे में बुकिंग और परिवहन की अनुमति नहीं है।

## घुमारवीं को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, 69 करोड़ के विकास कार्य समर्पित

**शिमला।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र की जनता को लगभग 69 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दो विकास कार्यों का उद्घाटन किया और पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने 4.82 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुलिस थाना घुमारवीं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 3.67 करोड़ रुपये की लागत से सीर खड्ड में बनाए गए चेक डैम और डाइक के कार्यों को भी जनता को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घुमारवीं के टिक्करी हेलिपैड के समीप 6.08 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने पुलिस थाना घुमारवीं में छह करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फैमिली क्वार्टर का भी शिलान्यास किया।

## आमजनों की हर जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी : कृषि मंत्री तिर्की

**रांची।** झारखंड के रांची जिला के मांडर प्रखंड में बुधवार को बेड़ो महादानी विवाह मंडप और प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) कार्यक्रम में जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में शामिल राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेता तिर्की ने कहा कि योजनाओं का लाभ जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि जनता की बड़ी जरूरतों के साथ-साथ छोटी-से-छोटी जरूरतों को भी पूरा किया जाए। मंत्री ने सीएसआर की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम में सीएसआर का प्रावधान किया, जिसके तहत कंपनियों को अपने मुनाफे का दो प्रतिशत सामाजिक विकास में खर्च करना होता है, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य में। उन्होंने कहा कि आज भी इस कानून से जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। मंत्री ने मनरेगा के नाम बदलने पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नाम बदलने के बजाय मजदूरी दर बढ़ाई जानी चाहिए थी। बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड ने कहा कि बेहतर जनप्रतिनिधित्व के कारण लोगों को उनका हक मिल रहा है और भविष्य में भी मांडर में सीएसआर कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान यह सहायता बेड़ो, इटकी, लापुंग और मांडर प्रखंड के लाभुकों को दी गई। महिलाओं को सिलाई मशीन और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी इंटरलॉकिंग मैट वितरित किया गया। मंत्री ने कहा कि ट्राई साइकिल से दिव्यांगजन आवागमन में सुविधा प्राप्त करेंगे, जबकि सिलाई मशीन से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मौके पर कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस नेता उपस्थित थे।

## स्पर्श गंगा अभियान के तहत निकाली रैली

**हरिद्वार।** स्पर्श गंगा अभियान के तहत बुधवार को एसएमजेएन पी जी कॉलेज की 'राष्ट्रीय सेवा योजना' इकाई ने जन जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को गंगा की स्वच्छता व निर्मलता के लिए जागरूक किया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि गंगा माँ हरिद्वार का गौरव है। इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ हमारी भी है।

कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पद्मावती तनेजा ने बताया कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है इसको स्वच्छ रखने के लिए लोगों का जागरूक होना अति आवश्यक है डॉ रुचिता सक्सेना ने गंगा सफाई के लिए छात्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया इस रैली में डॉ शिवकुमार चौहान, डॉ पूर्णिमा सुंदरियाल, प्रिंस क्षोत्रीय, डॉ पुनीता शर्मा, डॉ गौरव अग्रवाल, डॉ मनीषा पांडे, डॉ रेनू सिंह, नेहा, सोनिका, दीपिका आनंद, डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर रजनी सिंघल, रीना गिरी, नेहा, रचना गोस्वामी आदि उपस्थित रहे।

## इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को मिला केंद्रीय मंत्रियों का समर्थन

**जयपुर।** इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को लेकर केंद्र सरकार स्तर पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जय किशन रेड्डी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी तथा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भाजपा सीपी जोशी से लघु उद्योग भारती के शिष्ट मंडल ने भेंट कर इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का औपचारिक निमंत्रण दिया एवं आयोजन की प्रगति की जानकारी साझा की। इस दौरान सभी गणमान्यों ने इंडिया स्टोन मार्ट के प्रति सकारात्मक रुख जताते हुए आयोजन को अपना समर्थन दिया तथा कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति भी व्यक्त की।

शिष्ट मंडल में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नरेश पारीक, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं इंडिया स्टोन मार्ट के संयोजक नटवरलाल अजमेरा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण जाजोदिया एवं मीडिया प्रकोष्ठ के प्रताप राव शामिल रहे। इसी क्रम में जयपुर स्थित लघु उद्योग भारती कार्यालय में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की तैयारियों को लेकर कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आयोजन से जुड़ी विभिन्न समितियों का गठन कर सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। साथ ही अब तक की बुकिंग स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में स्टोन सेक्टर में डिजाइन प्रमोशन, इंडिया स्टोन मार्ट के लिए विकसित की जा रही मोबाइल ऐप तथा संभावित स्पॉन्सरशिप प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिससे आयोजन को और अधिक उद्योगोन्मुख एवं व्यावसायिक बनाया जा सके।

## समग्र, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ सरकार कर रही है कार्य : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

**भोपाल।** मध्य प्रदेश विधानसभा के ₹विकसित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश₹ विषय पर आयोजित विशेष सत्र में बुधवार को उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जेरियाट्रिक केयर-तीनों स्तरों पर समग्र, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को होने से रोकना। इसी उद्देश्य से प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्रिवेंटिव केयर को सशक्त किया गया है। निरोगी काया अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 1.19 करोड़ नागरिकों की हाइपरटेंशन, 1.22 करोड़ की डायबिटीज तथा 1.29 करोड़ लोगों की फैटी लीवर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए 39.4 लाख लोगों की ओरल कैंसर, 19.3 लाख महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर तथा 8.5 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की गई है।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में मध्यप्रदेश 6 पैरामीटर में देश में शीर्ष पर है। क्यूरेटिव केयर पर प्रकाश डालते हुए उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में टीबी स्क्रीनिंग एवं उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे इस बीमारी का

उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

अब तक लगभग 34 लाख हितग्राही उपचार का लाभ ले चुके हैं तथा योजना के माध्यम से 447 अंग प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निरंतर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे टर्शरी केयर सुविधाएँ जिला एवं संभाग स्तर तक सुलभ हो सकें।

आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे बहुमूल्य समय और जीवन दोनों की रक्षा हो सके। जेरियाट्रिक केयर के संबंध में राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए नियमित स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बीमारियों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही हो सके। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश का स्वास्थ्य मॉडल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर नागरिक-चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग-को समय पर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।

## दुकानदार से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

**जींद।** नरवाना के व्यापारी नरेश जैन से रविवार को पर्ची फैंक फायर कर 50 लाख रुपये की चौथ मांगने के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार की रात नरवाना सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह को सूचना मिली कि मुख्य आरोपित अनूप बेलरखां दातासिंह वाला बार्डर की तरफ बाइक पर जा रहा है।

जिस पर पुलिस ने आरोपित अनूप बेलरखां को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आपको चारों तरफ से घिरा देखकर अनूप बेलरखां ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। इसमें दो गोली अनूप बेलरखां की दोनों टांगों पर लगी और वह वहीं गिर गया। एक गोली सीआईए प्रभारी सुखदेव को छाती में लगी लेकिन बुलैट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वह बच गए। पुलिस ने अनूप बेलरखां को गिरफ्तार कर लिया और नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया। वहीं अनूप बेलरखां की बाइक चलाने वाले दूसरे बदमाश कैथल जिले के गांव सिरटा निवासी गौरव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को एसपी कुलदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इसमें जो मुख्य आरोपी अनूप जिसने फायर किया है, उस पर कुल मिला कर सात मामले दर्ज हैं। पहले उस पर पांच मामले दर्ज थे। अब उस पर दो और मामले दर्ज किए हैं। यह किसी गैंग से नही मिले हैं। अबतक की पूछताछ में सामने आ रहा है कि ये लोग डर का माहौल बना कर अपना नाम बदमाशी के मामले में चमकाना चाहते थे और अपनी गैंग बनाना चाहते थे।

हिसार, जींद में अनूप पर हत्या का प्रयास, स्नैचिंग के पांच मामले दर्ज थे। यह किसी गैंग से नही मिले हैं। अबतक की पूछताछ में सामने आ रहा है कि ये लोग डर का माहौल बना कर अपना नाम बदमाशी के मामले में चमकाना चाहते थे और अपनी गैंग बनाना चाहते थे। हिसार, जींद में अनूप पर हत्या का प्रयास, स्नैचिंग के पांच मामले दर्ज थे। उन्होंने बताया कि अनूप ने पुलिस पर प्वायंट टू थ्री बोर की गोलियां चलाई। इसमें खाली खोल और आठ जिंदा कारतूस मिले हैं और दूसरा प्वायंट थ्री वन फाइव फोर है।

## बांग्लादेशी नौसेना के हमले में लापता पांच मछुआरों में से दो के शव बरामद

**कोलकाता।** बांग्लादेशी नौसेना के हमले में लापता हुए पांच मछुआरों में से दो के शव बरामद कर लिए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में डूबे ट्रॉलर का पता मंगलवार को लगा था, जिसे अन्य ट्रॉलरों की मदद से किनारे की ओर लाया जा रहा था। इसी ट्रॉलर से दोनों शव बरामद हुए हैं।

मृतकों की पहचान संजीव दास और रंजन दास के रूप में हुई है। संजीव दास काकद्वीप के पश्चिम गंगाधरपुर के निवासी थे, जबकि रंजन दास पूर्व बर्धमान जिले के दुराजपुर के रहने वाले थे। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं, अन्य तीन मछुआरों की तलाश अभी भी जारी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बुधवार तड़के डूबे हुए ट्रॉलर को काकद्वीप के मैनापाड़ा डॉक पर लाया गया। ट्रॉलर से पानी निकालने के बाद इंजन रूम के अंदर से दोनों शव बरामद किए गए। इसकी सूचना काकद्वीप थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जल सीमा में घुसकर बांग्लादेशी नौसेना के एक जहाज ने काकद्वीप के मछुआरों के ट्रॉलर को टक्कर मार दी थी। इस घटना में 11 मछुआरे किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, जबकि पांच मछुआरे लापता हो गए थे। शुरुआत में इस घटना को एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन मछुआरों ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया है। मछुआरा सैफुद्दीन शेख का आरोप है कि जब बांग्लादेशी नौसेना का जहाज ट्रॉलर के बेहद करीब आया, तो जहाज से उन पर भाला फेंका गया। भाले की चोट ट्रॉलर के सामने खड़े मछुआरे राजदुल अली शेख को लगी, जिससे वह रक्तरंजित हालत में समुद्र में गिरकर लापता हो गया।

घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि बांग्लादेशी नौसेना भारतीय जल सीमा में कैसे घुसी और आखिर इस तरह का हमला क्यों किया गया? वहीं, लापता तीन मछुआरों के जीवित मिलने की उम्मीद अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

### मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह-2025 का किया शुभारंभ

# साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, दक्षता और कठिन प्रशिक्षण ही जवानों की पहचान बननी चाहिएः सीएम

**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 78 वर्ष से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा-संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह-2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने पीएसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। सीएम ने 78वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पीएसी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र के महापर्व 'चुनाव' को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है।

पीएसी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी, बल्कि देश के अंदर यूपी पीएसी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएसी बल के अदम्य साहस की चर्चा की। बताया कि 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और पांचों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए यूपी के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखा और आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से यूपी की बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की। संख्या, क्षमता, प्रशिक्षण, तकनीक के स्तर पर पीएसी की सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। अत्याधुनिक हथियारों व दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित करते हुए पीएसी को एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टीसेल लांचर, एंटी राइड गन, टियर गैस गन समेत अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान किए गए। सीएम योगी ने कहा कि पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए पूर्व में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को अपडेट करते हुए एबीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित कर उन्हें बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पद पर 1648 तथा आरक्षी के पद पर 15131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही यह भर्ती भी संपन्न होगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी व 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर सेवायोजन प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर पर 7 अभ्यर्थियों के सेवायोजन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है।

पीएसी में पदोन्नति के और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उपनिरीक्षकों के पदों में वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13313 आरक्षियों को पदोन्नति दी गई। 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस (पीएमएस) का चयन किया गया है। पीएसी के जवानों को बाजार से कम दाम पर सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन व 103 सब्सिडियरी कैंटीन संचलित हैं। पीएसी की 31 वाहिनी में 202 जवानों की आवासीय व्यवस्था के लिए जी प्लस 11, बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ाया गया है। इसमें से 18 वाहिनियों में कार्य पूर्ण हो चुका है और 13 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी वाहिनियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक व विशेष मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। सीएम योगी ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए यूपी में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की छह कंपनियों में 18 टीमें प्रदेश को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस को बढ़ावा देने के लिए दो प्रतिशत पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार द्वारा संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन व भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस 2024 पर खेल के बजट को 70 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। 2025 में प्रदेश पुलिस की टीम की ओर से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, दो रजत व तीन कांस्य पदक अर्जित किए गए। विभिन्न राष्ट्रीय व अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा 94 स्वर्ण, 70 रजत व 111 कांस्य पदक अर्जित किए गए।

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुरक्षा व सुशासन का बेहतर माहौल है और सरकार की अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। विगत 8 वर्ष में यूपी पुलिस बल में 2.19 लाख कार्मिकों की भर्ती की गई। इसमें 20 फीसदी महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यूपी पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिला पुलिस कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। टूटे खपरैल वाले भवन के स्थान पर हाईराइज भवन यूपी की अवस्थापना सुविधा के नए उदाहरण बने हैं। 7 जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना व साइबर सेल यूपी पुलिस की पहचान बनी है। फॉरेंसिक साइंस ईकोसिस्टम लखनऊ में यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही इंस्टीट्यूट ने देश में भी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पहचान बनाई है। प्रदेश में अत्याधुनिक 12 एफएसएल लैब बनकर तैयार हैं। छह नए प्रचलित हैं।

समारोह में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार आदि मौजूद रहे।

### तीन महिला पीएसी वाहिनी का किया गया गठन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0- महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के साथ ही स्वास्थ्य व सशक्तिकरण को भी बढ़ा रहा है। पहली बार यूपी की तीन अतिरिक्त महिला पीएसी वाहिनी (लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई और बदायूं में अवंती बाई) का गठन किया गया है। तीन अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में जालौन व मीरजापुर में भूमि प्राप्त हो चुकी है। बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई चल रही है। महिला उपनिरीक्षकों के 106, महिला आरक्षियों के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती कार्रवाई भी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने 17 नगर निगम में सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने और यूपीएसएसएफ की छह वाहिनी द्वारा प्रदेश भर में महत्वपूर्ण स्थलों व इमारतों की सुरक्षा में योगदान का भी जिक्र किया।

## वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड को वर्ष 2025 का रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला

▸▸ नगरीय सेवाओं और जीरो वेस्ट मॉडल में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान

**वाराणसी।** उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड को नगरीय सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार और कचरा शून्यकरण (जीरो वेस्ट) की दिशा में प्रभावी प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छावनी परिषद वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्यम मोहन और उनकी टीम को प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्त होने पर सीईओ सत्यम मोहन ने छावनी परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से सफाई कर्मियों को बधाई देते हुए उनके सहयोग और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान छावनी परिषद की कार्यप्रणाली, पर्यावरण हितैषी नीतियों और सामुदायिक सहभागिता आधारित विकास मॉडल का प्रमाण है। सीईओ ने बताया कि छावनी परिषद नागरिक सुविधाओं के निरंतर सुधार के लिए नए-नए नवाचारों पर कार्य कर रही है। रक्षा मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त होना जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों, विशेषकर सफाई मित्रों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है। उन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न कचरे को स्रोत पर ही पृथक करने, उसके सुरक्षित और व्यवस्थित संग्रहण तथा वैज्ञानिक प्रोसेसिंग के माध्यम से जीरो वेस्ट की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए निरंतर जन-जागरूकता अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिला है। पूर्व में छावनी परिषद डस्टबिन से कूड़ा एकत्र कर नगर निगम के करसड़ा स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट तक भेजती थी, जिससे भारी धनराशि व्यय होती थी। वर्तमान में वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड के सैनिटेशन पार्क में ही ठोस कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में छावनी परिषद द्वारा 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, सभी बड़े कम्युनिटी बिनों का पूर्ण निष्कासन और पुराने डंप साइट को हरित क्षेत्र में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। नगरीय प्रबंधन के इन समेकित प्रयासों का परिणाम यह रहा कि विगत एक वर्ष में वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में 7वीं रैंक प्राप्त की है और सेवा स्तर में निरंतर सुधार दर्ज किया है।

## सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत

**अमेठी।** जिले में संभवतः गैस सिलेंडर फटने से एक मकान ढह गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार देर रात भदेर-जामो रोड पर स्थित शिव महेश पांडे नामक व्यक्ति के मकान में हुई। पुलिस ने बताया कि गौरीगंज थानांतर्गत बस्तीदेई गांव के रहने वाले सतीश चंद तिवारी (37) की धमाके में मौत हो गई। जामो के रहने वाले एक और व्यक्ति बलराम चंद पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें गौरीगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान में स्थित कोल्ड ड्रिंक गोदाम के मालिक बलराम पांडे के अनुसार वह रात में गोदाम में रखे खातों को चेक करने गए थे, तभी यह घटना हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि मैं गेट का ताला खोल रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी इमारत गिर गई। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

## अपराधी की गोली मारकर हत्या

**प्रयागराज।** उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के गंगा नगर के मऊआइमा थाना अंतर्गत कंचनपुर में मंगलवार शाम प्रतापगढ़ के हिस्ट्रीशीटर अफसार अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। डीसीपी (गंगा नगर) कुलदीप गुनावत ने बताया कि प्रतापगढ़ के देल्हूपुर निवासी अफसार अहमद की आज शाम मऊआइमा थाना अंतर्गत कंचनपुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अफसार मोटरसाइकिल से आ रहा था। उन्होंने बताया कि अफसार अहमद हिस्ट्रीशीटर था और एक साल पूर्व नसीम अहमद नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में जेल गया था। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस दलों का गठन किया गया है।

## पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग को लेकर मेरठ बंद, वकीलों का प्रदर्शन

**मेरठ।** पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित कनरे की मांग को लेकर बुधवार को मेरठ समेत क्षेत्र के 22 जिलों में बंद का आह्वान किया गया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया था। मेरठ में सुबह से ही बंद का असर देखने को मिला, जहां कई प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रहीं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।

शहर के खैरनगर, सुमित बुढ़ाना गेट, जिमखाना मैदान समेत अनेक इलाकों में दुकान नहीं खुलीं। वकीलों ने सुबह से ही जगह-जगह धरना-प्रदर्शन किया और अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए। मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर महिला अधिवक्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। बंद को विभिन्न व्यापारिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन मिला। बेगमपुल चौराहे पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी बंद को पूर्ण समर्थन दिया। आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनीषा त्यागी और सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि बुधवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक चिकित्सकों ने ओपीडी सेवाएं बंद रखी हैं, हालांकि मरीजों की सुविधा को देखते हुए आपातकालीन सेवाएं जारी हैं।

# बेटे ने की माता-पिता हत्या, आरी से पांच टुकड़े कर शवों को नदी में फेंका

**जौनपुर।** जफराबाद थाना क्षेत्र में इकलौते बेटे ने अपने माथा-पिता की हत्या कर उनके शव को आरी से पांच टुकड़ों में काट कर नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। माता-पिता की हत्या के बाद युवक भीगायब हो गया। बाद में बहन की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी करने से माता-पिता नाराज थे। इसी वजह से युवक ने अपने दोनों की बेहरमी से हत्या की थी।

बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के लड़के अंबेश ने पूछताछ में बताया कि पारिवारिक कारणों और पैसे के लिए 8 दिसंबर की रात उसकी माता-पिता से बहस हुई थी और उसी दिनउसने गुस्से में सील बट्टे और धारदार हथियार से माता-पिता की हत्या कर दी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आरी से शवों को पांच टुकड़ों में काटा। उन्होंने बताया कि अंबेश के अनुसार उसने पहले अपनी माता को मारा। फिर पिता के शोर मचाने पर उसने उनकी भी हत्या कर दी। इसके रातभर घर की सफाई करने की और सुबह लगभग 5 बजे अंबेश ने शवों की बोरियों को गाड़ी में रखकर बेलवा घाट गोमती नदी में फेंक आया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंबेश ने बताया कि पैसे को लेकर बहनों से कोई विवाद नहीं था। वह कोई नशा भी नहीं करता था। अभी तक सीसीटीवी कैमरे से कोई फुटेज नहीं बरामद है। पुलिस ने पिता का शव बरामद कर लिया गया है जबकि मां के शव की तलाश जारी है। इस काम के लिय कुल 15 गोताखोरों की टीम लगाई गई है। पुलिस ने सिलबट्टा और आरी भीबरामद की ली है।

आरोपित अम्बेश शवों को ठिकाने लगाने के बाद अपने घर आ गया। इसके बाद अगले दिन 9 दिसंबर को अपने माता व पिता को खोजने का नाटक किया। उसने माता-पिता के लापता होने की खबर अपने परिचित, रिश्तेदारों को भी दी। इसी बीच अम्बेश कुमार भी 12 दिसंबर को खुद लापता हो गया। घर न आने पर वाराणसी जनपद के सिंधौरा थाना क्षेत्र कटौना गांव निवासी उसकी बहन वंदना किसी अनहोनी की आशंका से जफराबाद थाने पर पहुंची और अपने माता-पिता व इकलौते भाई के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई। इस पर पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू की।

इसी बीच आरोपित अम्बेश वाराणसी जाकर गंगा स्नान कर आया और कुछ दिनबाद वह घर के नजदीक आने लगा। इस पर पुलिस ने अंबेश को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में अम्बेश कुमार ने माता-पिता की हत्या की पूरी कहानी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक श्यामबहादुर केराकत के खरगसेनपुर गांव के रहने वाले थे। उनको यहां पर अपने ससुर स्वर्गीय रामनारायण ने अपनी संपति दे दिया था। श्यामबहादुर टाटा जमशेदपुर में रहते थे। वे रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात थे। उनके पास तीन पुत्रियां बड़ी वंदना कुमारी, अर्चना तथा सपना तथा एकमात्र पुत्र अम्बेश है।

अम्बेश दूसरे नम्बर पर था। सभी लड़कियों की शादी हो गयी थी। लगभग छह वर्ष से अम्बेश कुमार कोलकाता में रहकर कोई प्राइवेट नौकरी करता था। वही पर पांच वर्ष पूर्व उसने एक दूसरे सम्प्रदाय के लड़की से शादी कर लिया था। जिससे उसके एक लड़की व एक लड़का है। उसकी इस शादी को लेकर माता-पिता काफी नाराज थे। उन्होंने उसकी पत्नी को स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया था। इकलौते बेटे के इस तरह प्रेम विवाह करने से माता-पिता दुःखी रहते थे। पिता के पैसे से खरीदी कार से ही शवों को लगाया ठिकाने पिता के पैसे से अम्बेश कुमार ने 2022 में एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी। उसी कार से अम्बेश कुमार और उसका परिवार चलता था। जिस पिता ने बड़ी शौक से उस कार को खरीदा था, उसी कार से उसके इकलौता बेटे अम्बेश कुमार ने अपने माता और पिता की शवों को ठिकाने लगाने के लिए प्रयोग किया।

अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुश श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस व फारेंसिक टीम घर और कार की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।

## पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने पत्नी, दो बेटियों की हत्या कर शव घर में ही दफनाए

**मुजफ्फरनगर।** शामली जिले में एक पारिवारिक विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की कथित तौर पर हत्या कर दी और उनके शवों को अपने घर के अंदर ही दफना दिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना 10 दिसंबर को कांधला पुलिस थाना इलाके के घारी दौलत गांव में हुई थी लेकिन इसका पता मंगलवार शाम को चला। शामली के पुलिस अधीक्षक एन पी सिंह ने बताया कि आरोपी फारुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ तीन लोगों की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सिंह ने पत्रकारों को बताया, ''पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।''

पुलिस के मुताबिक, फारुख ने सबसे पहले अपनी पत्नी ताहिरा को उस समय गोली मारी, जब वह घर पर चाय बना रही थी। जब उनकी बड़ी बेटी आफरीन (12) ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसे भी गोली मार दी गई। एसपी ने बताया कि छोटी बेटी शैरीन (5) जब मौके पर पहुंची तो बाद में उसका गला घोंट दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बाद में घर के अंदर एक गड्ढा खोदा और अपराध को छिपाने के लिए शवों को उसमें दफना दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद हत्याओं का कारण बना।

इस बीच, घटना का पता चलने के बाद ताहिरा के परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और जब फारुख को पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था तो कथित तौर पर उस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने बताया कि घारी दौलत गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

## ईडी चार्जशीट खारिज होने के विरोध में भाजपा कार्यालय घेराव को जा रहे कांग्रेसी हिरासत में

**कानपुर।** नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र को राजधानी दिल्ली की स्थानीय अदालत द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया था। जिसके विरोध में बुधवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जाजमऊ चौराहे से हिरासत में ले लिया।

जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशन पर हम सभी लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। तभी जाजमऊ चेकपोस्ट के पास दो थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। हमारा रास्ता रोकते हुए हमें हिरासत में ले लिया। सरकार पूरी तरह से मनमानी तरीके से कार्य कर रही है। वह सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं। सरकार के इन अत्याचारों से डरने वाले नहीं है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेसी सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। काफी देर समझाने के बाद नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला को लखनऊ न जाने की हिदायत देते हुए पुलिस ने उन्हें उनके कार्यालय भेज दिया।

संदीप शुक्ला ने कहा कि यह पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। जिसे सरकार द्वारा जबरन दबाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है।

## कार के अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस जाने से दो युवकों की मौत

**बलिया।** जिले में मंगलवार देर रात को एक बेकाबू कार एक मकान में घुस गयी, जिससे दो युवकों की मौत हो गयी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सुखपुरा थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में 16 दिसंबर को रात लगभग साढ़े 11 बजे एक कार अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गयी। सुखपुरा से बलिया की तरफ जा रही कार की मकान से जोरदार टक्कर होने से अभिषेक (24) और रोहित (25) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सुजीत (21) और आदित्य (22) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद उस्मान ने बुधवार को बताया कि गंभीर रूप से दोनों घायलों का इलाज बलिया के जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में हो रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी युवक सुखपुरा थाना क्षेत्र के अपायल गांव के रहने वाले हैं।

## टी20आई रैंकिंग में तिलक वर्मा की छलांग, वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर कायम

**नई दिल्ली।** अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पुरुष टी20आई प्लेयर रैंकिंग में भारत के खिलाड़ियों को ताजा अपडेट में बड़ा फायदा हुआ है। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा दो स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान और मजबूत कर लिया है। तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20आई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। कटक में खेले गए पहले मैच में 26 रन बनाने के बाद उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में 62 रन की अहम पारी खेली और धर्मशाला में नाबाद 26 रन बनाए।

इसके दम पर उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और इंग्लैंड के जोस बटलर को पीछे छोड़ दिया। बल्लेबाजों की इस सूची में भारत के अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं। तिलक वर्मा की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग इस साल जनवरी में दूसरा स्थान रही है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने तीसरे मैच में टीम के कुल 117 रन में 61 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जिससे उन्हें आठ स्थान का फायदा हुआ और वह 29वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं, दूसरे टी20आई में मैच जिताऊ 90 रन बनाने वाले क्विंटन डी कॉक 14 स्थान की छलांग लगाकर 53वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती ने बीते हफ्ते खेले गए दो मैचों में दो-दो विकेट लेकर अपने खाते में 36 रेटिंग अंक जोड़े। उनके कुल अंक अब करियर के सर्वश्रेष्ठ 818 हो गए हैं। दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्हें धर्मशाला मैच में 2/13 के शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, चार स्थान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

वहीं, दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन 14 स्थान की छलांग लगाकर 25वें और लुंगी एनगिडी 11 स्थान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर, आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे को फायदा हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के दूसरे मैच में वेलिंगटन में उन्होंने 60 और 28 रन बनाए, जिससे उनकी टीम ने नौ विकेट से जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन के बाद कॉनवे बल्लेबाजों की सूची में सात स्थान ऊपर चढ़कर 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

# खेल मंत्री ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को किया सम्मानित

**नई दिल्ली।** केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय स्क्वैश टीम को सम्मानित किया। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलावन सेंथिलकुमार और अनाहत सिंह की मिश्रित टीम ने पिछले शनिवार चेन्नई में भारत को उसका पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब दिलाकर इतिहास रच दिया। यह जीत भारत का पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 संस्करण में कांस्य पदक रहा था।

फाइनल मुकाबले में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराया। इसके साथ ही भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला चौथा देश बन गया, इससे पहले यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र को मिली थी। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए डॉ. मांडविया ने इसे "भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का क्षण" बताया। उन्होंने कहा, "भारत खेल क्षेत्र में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है।" उन्होंने आगे कहा, "अपने ही देश की धरती पर स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतना बेहद गर्व की बात है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। मुझे विश्वास है कि खेल क्षेत्र का यह विकास आगे भी देश को नई सफलताएं दिलाता रहेगा।"

भारत के शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ( टॉप्स) का भी लाभ मिला है, जिसने उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के जरिए उनकी तैयारी को मजबूत किया है। टीम की सबसे युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने चेन्नई में मिले दर्शकों के समर्थन को अहम बताया। 17 वर्षीय अनाहत ने कहा, "मैंने पहली बार वर्ल्ड कप में अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेला। यह मेरे लिए शानदार सीखने का अनुभव रहा। मैं चेन्नई के दर्शकों का लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद करती हूं।" अब भारतीय टीम की नजरें एशियन गेम्स 2026 और उसके बाद लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 पर हैं, जहां स्क्वैश पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में शामिल होगा। जापान में अगले साल होने वाले एशियन गेम्स से पहले पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जोशना चिनप्पा भी आशावादी हैं।

39 वर्षीय जोशना ने कहा, "हम कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और वर्ल्ड कप का अनुभव बेहद शानदार रहा। इससे एशियाड के लिए हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेहतरीन फिटनेस बनाए रखूं और खेलों के लिए क्वालिफाई करूं।"

## लियोनेल मेस्सी को उम्मीद, भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल होगा

**नई दिल्ली।** स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान शानदार मेहमाननवाजी के लिए आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भारत का फुटबॉल में भविष्य उज्जवल होगा। मेस्सी ने अपने भारत दौरे में चार शहरों का दौरा किया और इस दौरान हजारों प्रशंसक अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे।

जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वंतारा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का दौरा करने के लिए भारत में अपना प्रवास एक दिन के लिए बढ़ाने के बाद मेस्सी बुधवार को मियामी के लिए रवाना हो गए। इस 38 वर्षीय फुटबॉलर ने इंस्टाग्राम पर दौरे का एक मिनट का क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वह भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और कई युवा फुटबॉलरों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

मेस्सी ने कहा, "दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता का दौरा अद्भुत रहा। पूरे दौरे के दौरान आपने जिस गर्मजोशी से स्वागत, उदार आतिथ्य सत्कार और प्रेम भाव दिखाया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है।" मेस्सी ने ऐसे समय में भारतीय फुटबॉल को शुभकामना दी है जबकि वह अपने बुरे दौर से गुजर रही है। कोई व्यावसायिक साझेदार नहीं मिलने के कारण घरेलू सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है जबकि राष्ट्रीय टीम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मेस्सी ने इस यात्रा के दौरान कोई भी प्रतिस्पर्धी फुटबॉल मैच नहीं खेला। इस दौरे के दौरान उनके साथ उरुग्वे के महान खिलाड़ी और उनके करीबी मित्र लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल भी थे। मेस्सी का दौरा कोलकाता से शुरू हुआ था जहां राजनेताओं और अधिकारियों ने उन्हें घेर दिया जिससे स्थिति खराब हो गई क्योंकि हजारों रुपये में टिकट खरीदने वाले प्रशंसकों को इस दिग्गज खिलाड़ी की स्पष्ट झलक देखने को नहीं मिली। इससे उत्तेजित होकर दर्शकों ने साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

मेस्सी ने दिल्ली में अपने दौरे के अंतिम चरण में कहा, "हम इस प्यार को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम निश्चित तौर पर लौटेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मैच खेलने या किसी अन्य अवसर पर वापसी करेंगे। हम निश्चित तौर पर भारत का फिर से दौरा करेंगे।

## श्रीलंका ने आर श्रीधर को टी20 विश्व कप तक फील्डिंग कोच नियुक्त किया

**कोलंबो।** श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने बुधवार को भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप के आखिर तक अपनी राष्ट्रीय टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया। श्रीधर 2014 से 2021 तक भारत के फील्डिंग कोच रहे थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के राष्ट्रीय हाई परफार्मेंस सेंटर में 10 दिन का विशेष फील्डिंग शिविर भी आयोजित किया था।

श्रीलंका क्रिकेट ने विज्ञप्ति में कहा कि एसएलसी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के समापन तक श्रीलंका राष्ट्रीय टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर की नियुक्ति की घोषणा करता है। विज्ञप्ति के अनुसार बीसीसीआई के लेवल तीन के कोच श्रीधर 2014 से 2021 तक भारतीय राष्ट्रीय पुरुष टीम के फील्डिंग कोच रहे और उन्होंने 300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दी।

इसमें कहा गया है कि अब वह श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम की फील्डिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा पाकिस्तान और इंग्लैंड के आगामी दौरों के दौरान खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे। इसके बाद आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी शुरू होगी। श्रीधर की नियुक्ति 11 दिसंबर से 10 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान श्रीलंका पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला और उसके बाद टी20 विश्व कप खेलेगा।

भारत और श्रीलंका टी20 विश्व कप के संयुक्त मेजबान हैं। श्रीधर ने कहा कि मैं टीम के अंदर ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करूंगा जिसे खेल भावना, जागरूकता और यह खेल खेलने का गर्व स्वाभाविक रूप से तैयार हो सके। फील्डिंग तभी फलती-फूलती है जब खिलाड़ी गेंद से, एक-दूसरे से और वर्तमान क्षण से जुड़ाव महसूस करते हैं।

## एशेज: कैरी और ख्वाजा के नाम पर रहा तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन

**एडिलेड।** विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी के करियर के तीसरे शतक और स्टीव स्मिथ के अस्वस्थ होने के कारण अंतिम समय में टीम में जगह बनाने वाले उस्मान ख्वाजा की 82 रन की लाजवाब पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुरुआती झटकों से उबरकर आठ विकेट पर 326 रन बनाए। कैरी ने अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए ऐसे समय में क्रीज पर कदम रखा जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 94 रन था। उन्होंने 143 गेंद का सामना करके 106 रन बनाए जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल है।

इससे पहले ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटकों से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभवी बल्लेबाज को उनके 39वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर स्मिथ के अस्वस्थ होने के कारण बाहर हो जाने से जल्दबाजी में टीम में शामिल किया गया। ख्वाजा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जब वह पांच रन पर खेल रहे थे तब उन्हें जीवनदान मिला। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाकर मार्नस लाबुशेन (19) के साथ 61 रन की और कैरी के साथ 91 रन की दो महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाई। कैरी ने जोश इंग्लिश (32) के साथ 59 रन और इस मैच में वापसी करने वाले कप्तान पैट कमिंस (13) के साथ 50 रन की साझेदारी की। दिन का खेल समाप्त होने के समय मिशेल स्टार्क 33 रन पर खेल रहे थे जबकि नाथन लियोन ने अभी अपना खाता नहीं खोला है।

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 29 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। उनके अलावा तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स और स्पिनर विल जैक्स ने दो-दो विकेट हासिल किए हैं। कैरी और ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी की और मैच का पहला दिन काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के नाम सुनिश्चित किया। इन दोनों ने स्लॉग-स्वीप शॉट खेल कर अपना विकेट गंवाया। ख्वाजा ने जैक्स की गेंद पर स्लॉग-स्वीप शॉट खेला जो सीधे आउटफील्ड में जोश टोंग के हाथों में चला गया।

कैरी ने भी इसी स्पिनर पर स्लॉग-स्वीप करने के प्रयास में विकेटकीपर जेमी स्मिथ को कैच दिया। इंग्लैंड ने सुबह और दोपहर के सत्रों में शुरुआती ओवरों में दो-दो विकेट लिए। आर्चर ने नौवें ओवर में जेक वेदरल्ड (18) को आउट करके ट्रैविस हेड (10) के साथ उनकी पहले विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने लंच के बाद पहले ओवर में लाबुशेन और कैमरन ग्रीन (00) को आउट किया जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 94 रन हो गया था। हेड और वेदरल्ड की ऑस्ट्रेलिया की नई सलामी जोड़ी जब सहजता से आगे बढ़ रही थी तब आर्चर ने अपने पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर वेदरल्ड को आउट किया। उनकी लगभग लगभग 148 किमी प्रति घंटे (92 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से फेंकी गई गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछल गई और विकेट के पीछे आसानी से कैच हो गई। कार्स ने अगले ओवर में हेड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 33 रन कर दिया। हेड ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन शॉर्ट कवर पर जैक क्रॉली ने शानदार कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया।

ख्वाजा भी जल्दी पवेलियन लौट जाते लेकिन हैरी ब्रूक ने 16वें ओवर में उनका कैच छोड़ दिया। उन्होंने इसका फायदा उठाकर प्रवाहमय बल्लेबाजी की और अपनी पारी में 10 चौके लगाए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने रविवार को सिडनी के बोंडी बीच पर हुए हमले में मारे गए 15 लोगों और घायल लोगों के सम्मान में काली पट्टी बांधी। यह हमला हनुकाह की शुरुआत का जश्न मना रहे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था।

## वैश्विक व्यापार को शुल्क के जरिये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है: सीतारमण

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि शुल्क और अन्य उपायों के जरिये वैश्विक व्यापार का हथियार के तौर पर इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत को ऐसे में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती देश को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक स्तर पर अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यापार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि शुल्क और अन्य कई उपायों के जरिये व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है।

भारत को इसलिए सावधानीपूर्वक बातचीत करनी होगी और केवल शुल्क से निपटना काफी नहीं होगा...बल्कि मुझे लगता है कि हमारी समग्र आर्थिक मजबूती ही हमें वह अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारत को यह कहकर उपदेश दिया जा सकता है कि आप (भारत) बहुत अंतर्मुखी हैं, आप शुल्क के बादशाह हैं इत्यादि। हालांकि शुल्क का दुरुपयोग हथियार के रूप में किया गया है।" मंत्री ने कहा कि भारत का इरादा कभी भी शुल्क का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने का नहीं रहा। सीतारमण ने कहा कि भारत ने केवल अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा की है ताकि वे ऐसे हालात से बच सकें जहां कोई

### वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए केंद्र ने स्पष्ट लक्ष्य तय किए,राज्य भी अनुसरण करें: वित्त मंत्री

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अपने ऋण स्तर को कम किया है। उन्होंने साथ ही राज्यों से भी इन्हें लागू करने का आह्वान किया है। सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 से राजकोषीय घाटे के साथ-साथ ऋण स्तर पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों को भी अपने ऋण स्तर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि देश 2047 तक एक 'विकसित राष्ट्र' बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट तैयार करने में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राजकोषीय प्रबंधन सभी के लिए पारदर्शी हो एवं जवाबदेही के उच्च मानकों को पूरा करे।

परिणामस्वरूप, कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से हम ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने में सक्षम हुए हैं। उस समय यह 60 प्रतिशत से अधिक हो गया था। अब यह घटता हुआ प्रतीत हो रहा है।

वैश्विक महामारी के बाद भारत का ऋण-जीडीपी अनुपात बढ़कर 61.4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से इसे 2023-24 तक घटाकर 57.1 प्रतिशत करने में मदद मिली। सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष यह घटकर 56.1 प्रतिशत हो जाएगा। ऋण-जीडीपी अनुपात, किसी देश के कुल कर्ज (सरकार व निजी) की उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से तुलना करने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैमाना है। सीतारमण ने राज्यों से केंद्र सरकार की तरह ही राजकोषीय प्रबंधन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया जिसने हर साल ऋण स्तर को कम किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जब तक ऋण-जीएसडीपी अनुपात को बेहतर ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता और इसे एफआरएमबी सीमाओं के भीतर नहीं रखा जाता और वर्षों से जमा हो रहे उच्च ब्याज दरों वाले ऋण को कम नहीं किया जाता (जिसे कई राज्य चुकाने में असमर्थ हैं).. तब तक आप ऋणों को चुकाने के लिए उधार लेते रहेंगे, विकासात्मक व्यय के लिए उधार नहीं ले पाएंगे। राजकोषीय परिदृश्य में यह एक गलत रणनीति है।

## रुपया अबतक के सबसे निचले स्तर से उबरा, 55 पैसे चढ़कर 90.38 प्रति डॉलर पर बंद

**मुंबई।** रुपया बुधवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में अपने अबतक के सबसे निचले स्तर से उबरने में कामयाब रहा और 55 पैसे चढ़कर 90.38 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। केंद्रीय बैंक के संभावित आक्रामक हस्तक्षेप से रुपया बढ़त में रहा। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में हाल की गिरावट मुख्य रूप से बाहरी कारकों के कारण हुई है, न कि घरेलू आर्थिक कमजोरी की वजह से।

बदलते आर्थिक एवं भू-राजनीतिक संकेतों के बीच विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापक अस्थिरता जारी रहने का अनुमान है। अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में आशाजनक प्रगति न होने और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है, जबकि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के करीब रहने से घरेलू मुद्रा को निचले स्तर पर समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.05 पर खुला।

इसके बाद इसने कुछ हद तक खोई हुई बढ़त हासिल की और 89.96 प्रति डॉलर के दिन के उच्च स्तर को छुआ जो पिछले बंद भाव से 97 पैसे की बढ़त दर्शाता है। अंत में रुपया 90.38 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 55 पैसे अधिक है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहली बार 91 के स्तर को पार कर 91.14 प्रति डॉलर पर पहुंच गया था। अंत में 90.93 पर बंद हुआ था।

## शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 120 अंक कमजोर

**मुंबई।** विदेशी निवेशकों की निरंतर बिकवाली के दबाव में घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 120 अंकों की गिरावट दर्ज की गई जबकि निफ्टी करीब 42 अंक फिसल गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 120.21 अंक यानी 0.14 प्रतिशत गिरकर 84,559.65 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान एक समय यह 263.88 अंक टूटकर 84,415.98 के स्तर पर आ गया था। इसी तरह, एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 41.55 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,818.55 अंक पर बंद हुआ, जो एक सप्ताह का निचला स्तर है। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन और एशियन पेंट्स के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। इसके उलट, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी के शेयर बढ़त में रहे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 2,381.92 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,077.48 करोड़ रुपये की खरीदारी की। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का क़ॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के बाजार बढ़त में बंद हुए।

यूरोपीय बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिका के अधिकांश बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.12 प्रतिशत चढ़कर 60.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। मंगलवार को सेंसेक्स 533.50 अंक टूटकर 84,679.86 अंक और निफ्टी 167.20 अंक गिरकर 25,860.10 अंक पर बंद हुआ था।

## किसानों का संगठन नासिक में 'राष्ट्रीय प्याज केंद्र' करेगा स्थापित

**नासिक।** महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ नासिक में एक 'राष्ट्रीय प्याज केंद्र' स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य किसानों को प्याज के उत्पादन, इसके मूल्य निर्धारण एवं व्यापारिक निर्णयों पर अधिक नियंत्रण देना है। संघ के संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले ने रविवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह केंद्र नासिक जिले के सिन्नर तालुका के जयगांव गांव में शुरू में दो एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। इसमें भविष्य में विस्तार की गुंजाइश होगी। गौरतलब है कि नासिक जिले में स्थित लासलगांव कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) एशिया में प्याज का सबसे बड़ा बाजार है। दिघोले ने कहा कि राष्ट्रीय प्याज केंद्र', प्याज की खेती को एक अनिश्चित एवं कर्ज पर आधारित गतिविधि से एक स्थिर, लाभदायक एवं टिकाऊ व्यवसाय में तब्दील कर देगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले चरण की लागत करीब पांच करोड़ रुपये होने की संभावना है जिसे किसानों के योगदान से जुटाया जाएगा।

## भारत,ओमान आज मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर

**नई दिल्ली।** भारत और ओमान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। मोदी मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया पहुंचे और अदीस अबाबा से ओमान के लिए रवाना होंगे।

अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मस्कट पहुंच चुके हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भी ओमान पहुंचेंगे। मुक्त व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। इस पर बातचीत औपचारिक रूप से नवंबर 2023 में शुरू हुई जो इस वर्ष संपन्न हो गई। इस प्रकार के समझौते में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी हद तक कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में ओमान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत का पहले से ही जीसीसी के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ इसी तरह का समझौता है जो मई 2022 में लागू हुआ था। भारत और कतर भी जल्द ही व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर) था।

भारत के प्रमुख आयात पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया हैं जिनकी कुल आयात में हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। अन्य प्रमुख उत्पादों में प्रोपलीन और एथिलीन पॉलिमर, पेट कोक, जिप्सम, रसायन, लोहा और इस्पात तथा अपरिष्कृत एल्युमीनियम शामिल हैं। ओमान को होने वाले भारतीय निर्यात का लगभग 16.5 प्रतिशत हिस्सा उन वस्तुओं का निर्यात है जिन पर पहले से ही शुल्क-मुक्त पहुंच है। इन वस्तुओं में गेहूं, बासमती चावल, फल, सब्जियां, दवाएं, मछली, चाय और कॉफी शामिल हैं। इस 16.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के निर्यात की कीमत करीब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।

# दिव्या ने भाई के साथ गुनगुनाया पुराना गीत 'दिल तड़प तड़प के'

**मुंबई।** हाल ही में बालीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने एक खास वीडियो पोस्ट किया। दिव्या ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया, जिसमें दोनों भाई-बहन बेहद सहज और आत्मीय अंदाज में नजर आते हैं। इस वीडियो में वह अपने भाई राहुल के साथ बैठकर हिंदी सिनेमा का मशहूर गीत 'दिल तड़प तड़प के' गुनगुनाती नजर आ रही हैं। गाना गाते हुए उनके चेहरे पर अपनापन और सुकून साफ झलक रहा है। वीडियो के साथ दिव्या ने भावुक लेकिन हल्के-फुल्के अंदाज में कैप्शन लिखा कि भाई राहुल के साथ बैठकर गाने के जरिए दिनभर की थकान उतारना उन्हें बहुत सुकून देता है। उन्होंने यह भी लिखा कि उनका भाई इशारों-इशारों में सुर पकड़ने में हमेशा मदद करता है। कैप्शन के अंत में 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' लिखकर उन्होंने भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते को और खास बना दिया। साथ ही, मजाकिया लहजे में उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गायिकी को जज न किया जाए। दिव्या दत्ता का यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उनके दोस्त भी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे दिल को छू लेने वाला पल बताया, तो कुछ ने भाई-बहन के रिश्ते की गर्माहट की सराहना की। यह वीडियो न सिर्फ एक पारिवारिक पल को दर्शाता है, बल्कि पुराने दौर के संगीत के प्रति दिव्या के प्रेम को भी उजागर करता है। जिस गीत को दिव्या और उनके भाई ने गुनगुनाया, वह हिंदी सिनेमा का सदाबहार गीत 'दिल तड़प तड़प के' है। यह गीत साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म 'मधुमती' का है। इस गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर और महान गायक मुकेश कुमार ने अपनी आवाज दी थी, जबकि इसका संगीत दिग्गज संगीतकार सलिल चौधरी ने तैयार किया था। फिल्म में इस गीत को दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला पर फिल्माया गया था, जिनकी जोड़ी ने पर्दे पर रोमांस को एक अलग ऊंचाई दी थी। फिल्म 'मधुमती' का निर्देशन और निर्माण बिमल रॉय ने किया था और यह अपने समय की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, प्राण और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले थे, जिनमें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान भी शामिल है। पुनर्जन्म की थीम पर आधारित यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है।

## यह सिर्फ फिल्म नहीं, हर देशभक्त के लिए लव लेटर, धुरंधर देख बोलीं

# प्रीति जिंटा

**मुंबई।** फिल्मी दुनिया में साल का अंतिम समय 'धुरंधर' के नाम रहा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ लोगों के दिलों पर भी राज कर रही है। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार चुकी है। फिल्म देखने वाले अधिकतर दर्शक इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने 'धुरंधर' देखी और फिल्म को मास्टरपीस बताया। अभिनेत्री का कहना है कि वे एक बार नहीं, बल्कि कई बार फिल्म देख सकती हैं। फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपनी खुशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से शेयर की और पूरी फिल्म की स्टारकास्ट की तारीफ करते हुए फिल्म निर्माता आदित्य धर को स्पेशल बताया। उन्होंने लिखा, "आज का दिन बहुत मजेदार था। बहुत दिनों बाद मैंने अकेले थिएटर में फिल्म देखी। दोपहर का शो हाउसफुल था और वाह, क्या जबरदस्त अनुभव था और ये उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो मैंने बहुत समय बाद देखी है। बिल्कुल रॉ, रियल और मास्टरपीस। फिल्म के सभी किरदारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने आगे लिखा, "दिल को छू लेने वाला और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला म्यूजिक बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा आदित्य धर के डायरेक्शन से प्यार हो गया। इतनी मेहनत से और फिर भी इतने दिल से बनाया गया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हर उस अनजान आदमी, औरत और देशभक्त के लिए एक लव लेटर है जिसने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। साढ़े तीन घंटे पलक झपकते ही बीत गए और मैं इसे दोबारा देखने के लिए तैयार हूं। प्रीति को फिल्म के निर्माता और निर्देशक आदित्य धर के काम से प्यार हो गया है, और वे खुद उन्हें कॉल करके फिल्म का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हैं। उन्होंने सभी से फिल्म को देखने की अपील की है।

# शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी अफवाहों पर नागार्जुन ने तोड़ी चुप्पी

अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2025 को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई है। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं तेज हैं कि यह स्टार कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है। हालांकि, इन अफवाहों पर अब तक शोभिता या नागा चैतन्य में से किसी ने भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब इस मामले पर नागार्जुन का बयान सामने आया है, जिसने चर्चाओं को और हवा दे दी है। दिए एक इंटरव्यू में नागार्जुन से पूछा गया कि क्या वह सच में दादा बनने वाले हैं। इस सवाल पर पहले तो अभिनेता कुछ पल सोचते नजर आए, फिर हल्की मुस्कान के साथ वहां से जाने की कोशिश करने लगे। जब उनसे दोबारा सवाल किया गया, तो नागार्जुन ने हंसते हुए कहा, ₹सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा।₹ उन्होंने न तो इन खबरों की पुष्टि की और न ही साफ तौर पर खंडन किया। नागार्जुन के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। फैंस अब कयास लगा रहे हैं कि अफवाहों में सच्चाई हो सकती है और कई लोग पहले से ही शोभिता और नागा चैतन्य को बधाइयां देने लगे हैं। गौरतलब है कि शोभिता और नागा चैतन्य ने 2022 में डेटिंग शुरू की थी। इसके बाद 2024 में सगाई कर उन्होंने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया। शोभिता से पहले नागा चैतन्य की शादी सामंथा रुथ प्रभु से हुई थी, जो 2021 में खत्म हो गई थी। वहीं, सामंथा ने इसी महीने दिसंबर में फिल्म निर्माता राज निदिमोरू से शादी की है।

# विदेश

## संक्षिप्त खबरें

### पासपोर्ट दुरुपयोग मामले में रवि लामिछाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

**काठमांडू।** पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट दुरुपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई। युवराज पौडेल की ओर से दो वर्ष पहले दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, जिसमें उन्होंने रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। पौडेल ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के उस निर्णय को कानून के विपरीत बताया था, जिसमें लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले पुलिस और सरकारी वकील कार्यालय भी पासपोर्ट प्रकरण में लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला कर चुके थे। रिट याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक रहते हुए स्वयं को नेपाली नागरिक बताना और पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करना पासपोर्ट अधिनियम, 2024 की धारा 5(ख) के विरुद्ध एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में, इस तथ्य पर विवाद न होने के बावजूद रवि लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण और अनुचित है। युवराज पौडेल ने यह भी आरोप लगाया है कि महान्यायाधिवक्ता ने यह निष्कर्ष निकालते समय कि पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में रवि लामिछाने की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया।

### ट्रंप ने 20 और देशों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध बढ़ाया

**वाशिंगटन।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंधों को और सख्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 20 और देशों के साथ-साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी प्रतिबंध सूची में जोड़ दिया गया है। इस कदम से अमेरिका आने या इमिग्रेट करने वालों पर लगाई गई सीमाएं काफी बढ़ गई हैं। अब कुल पांच देशों पर अमेरिका में प्रवेश का पूरी तरह प्रतिबंध है। वहीं 15 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक लगाई गई है। प्रशासन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करने वाले लोगों की यात्रा पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम अमेरिका में प्रवेश से जुड़े नियमों को और कड़ा करने के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। अधिकारियों ने हाल ही में व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड जवानों पर गोलीबारी के आरोपी एक अफगान नागरिक की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया। हालांकि, इन प्रतिबंधों में कुछ छूट भी दी गई है। जिन लोगों के पास पहले से वैध अमेरिकी वीजा है, उन पर यह रोक लागू नहीं होगी। स्थायी निवास की अनुमति वाले लोग, राजनयिक, खिलाड़ी और कुछ अन्य श्रेणियों के वीजा धारक भी इससे बाहर रखे गए हैं।

# भारत-इथियोपिया के रिश्ते अब कूटनीतिक साझेदारी के स्तर पर: मोदी

**अदीस अबाबा/नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे का आज दूसरा दिन है। जहां उन्होंने पहले इथियोपिया के अदीस अबाबा में स्थित अदवा विजय स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद इथियोपिया की संयुक्त संसद के सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और इथियोपिया के खास संबंद और मजबूत दोस्ती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कल मुझे इथियोपिया की तरफ से जो सम्मान मिला- निशान-ए-इथियोपिया उसके लिए मैं प्रधानमंत्री अबी अहमद का आभारी हूं। हम इथियोपिया सरकार और प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इथियोपिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। यहां इतिहास पहाड़ियों, गांवों और लोगों के दिलों में भी दिखता है। आज इथियोपिया अपने पैरों पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि पुराने और नए का संगम यह संतुलन इथियोपिया की असम मजबूती है। यह ऊर्जा हम भारतीयों के लिए काफी परिचित है।

इस दौरान उन्होंने भारत और इथियोपिया के मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा

कि भारत की कंपनियों ने इथियोपिया में काफी व्यापार की संभावनाएं देखी हैं। यहां भारतीय कंपनियों ने 5 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है और यहां कई लोगों को नौकरियां मुहैया कराई हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे व्यापारिक रिश्तों में अभी काफी संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते अब कूटनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाई जाएगी।

इससे हमारी अर्थव्यवस्थाएं साझा तौर पर बढ़ेंगी। खनन, हरित ऊर्जा से लेकर कई और क्षेत्रों में हम साथ काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा में भी हम अपने सहयोग को बढ़ाएंगे और खाद्य सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हम कृषि क्षेत्र के लिए भी काफी काम कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कर सकते हैं। अदीस अबाबा हो या अयोध्या। भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। यह कहता है कि राजनीति, सीमा, कई मतभेदों के बाद भी हम साथ खड़े हैं तो हमारे भाग्य भी साझा हैं। भारत और इथियोपिया जलवायु में गर्म हैं तो रिश्तों में भी एक गर्मी साझा करते हैं।

### 2000 साल पहले बने थे भारत-इथियोपिया के बीच रास्ते: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि करीब 2000 साल पहले भारत और इथियोपिया के बीच समुद्र के रास्ते संपर्क बने थे। उस समय भारतीय महासागर के जरिए व्यापारी मसाले और सोना लेकर आते-जाते थे। लेकिन यह व्यापार सिर्फ सामान तक सीमित नहीं था, बल्कि विचारों और जीवनशैली का भी आदान-प्रदान होता था। उन्होंने कहा कि अदीस अबाबा और धोलावीरा जैसे बंदरगाह सिर्फ व्यापार केंद्र नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने वाले पुल थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि आधुनिक इतिहास में भारत और इथियोपिया के रिश्ते और मजबूत हुए। उन्होंने कहा कि 1941 में इथियोपिया की आजादी के लिए भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।

### भारत-इथियोपिया के आर्थिक रिश्तों पर भी बोले पीएम

इसके बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में शामिल हैं। अब तक भारतीय कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में 5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुकी हैं, जिससे 75 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और इथियोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अब रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा।

### भारत-इथियोपिया का एक मंत्र: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र हमारा नारा है। उन्होंने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगीत अपने देश का मां के तौर पर जिक्र करता है। यह हमें हमारी संस्कृति, विरासत, राष्ट्रीय सुंदरता और जमीन की सुरक्षा का संदेश देते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हजारों भारतीय टीचर इथियोपिया आए हैं, वे बच्चों को एडिस अबाबा से लेकर अलग-अलग शहरों में पढ़ा रहे हैं। वे इथियोपियाई स्कूल आते हैं और इथियोपियाई लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज इथियोपिया के कई अभिभावक भारत के शिक्षकों के बारे में काफी अच्छी बातें करते हैं। जैसे भारत के शिक्षक इथियोपिया आते हैं वैसे ही इथियोपिया के छात्र भी भारत आते हैं और वे आधुनिक इथियोपिया के निर्माण का सपना संजोते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वे हमारे पीपल टू पीपल कनेक्ट को बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वे इथियोपियाई खाने से भारत का परिचय कराते हैं। चूंकि हम भारतीय थाली खाना पसंद करते हैं इसलिए इथियोपिया का खाना भी यहां के खाद्य पदार्थों की वजह से हमें अपना लगता है।

# नेपाल में हिमालय स्वच्छता अभियान शुरू, पर्वतारोहियों के लिए पंचवर्षीय योजना

**काठमांडू।** नेपाल सरकार के संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालयने हिमालय को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू करते हुए पंचवर्षीय योजना घोषित की है। यह योजना पर्वतों की सामर्थ्य या वहन क्षमता के आधार पर पर्वतारोहियों की संख्या और चढ़ाई का समय तय करेगी। अब पर्वतारोहण के लिए मांग के अनुसार असीमित अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य पर्वतों पर अत्यधिक संख्या में अनुमति दिए जाने से समग्र व्यवस्थाओं में समस्या आने की शिकायतें मिल रही हैं।

इन जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने कचरा प्रबंधन में सख्ती, जमानत प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देने तथा कचरा निष्कासन पर कड़ाई जैसे कार्यक्रमों को समेटते हुए नई कार्ययोजना (2025/2030) घोषित की है। मंत्रालय का तर्क है कि यदि पर्वतारोहियों और पदयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मल-मूत्र, मृत शरीर, कैन, बोतल, प्लास्टिक,

टेंट, पाउच और थैलों जैसी वस्तुओं का उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे हिमाली क्षेत्रों के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण पंचवर्षीय योजना की जरूरत पड़ी। विश्व में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 14 पर्वतों में से आठ नेपाल में स्थित हैं। नेपाल में 28 हिम शृंखला हैं, जो 6,000 से अधिक छोटी-बड़ी नदियों और धाराओं का प्रमुख स्रोत हैं। आंकड़ों के अनुसार नेपाल भर में 5,358 झीलें और 2,232 हिमताल हैं। 6,000 मीटर से ऊपर के 1,310 शिखर नेपाल में हैं। हालांकि, पर्वतारोहियों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय पर्यावरण, जैव विविधता, प्रदूषण और कचरा उत्सर्जन जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं।

मंत्रालय के अनुसार, यदि मौजूदा दर से तापमान बढ़ता रहा तो इसी शताब्दी के भीतर 36 प्रतिशत तक और यदि कार्बन उत्सर्जन वर्तमान स्तर पर ही बना रहा तो 64 प्रतिशत तक बर्फ पिघलने का जोखिम है। मंत्रालय का कहना है कि पर्वतारोहण के शुरुआती चरणों में पर्वतारोहियों ने कचरा प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे हिमालय में कचरा जमा होता गया। अत्यधिक ठंड के कारण यह कचरा वर्षों तक जस का तस बना रहता है और आज भी पर्वतारोहियों को कचरे पर कदम रखते हुए पर्वत चढ़ने की मजबूरी है।

# एआई सम्मेलन 'ग्लोबल साउथ' के लिए अंतरराष्ट्रीय एआई एजेंडे को आकार देने का मौका: भारत

**संयुक्त राष्ट्र।** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने यहां कहा कि अगले साल की शुरुआत में भारत में होने वाले 'एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन में 'ग्लोबल साउथ' के देशों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंडे को सक्रियता से आकार देने का अवसर मिलेगा। 'ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है, जो प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के मामले में कम विकसित माने जाते हैं। ये देश मुख्यतः दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित हैं। इसमें अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस 19-20 फरवरी को नयी दिल्ली में आयोजित होने वाले 'इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट' में भाग लेंगे। पहली बार 'ग्लोबल साउथ' के किसी देश में एआई सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले बलेटचली पार्क (ब्रिटेन), सियोल और पेरिस में इसी तरह के वैश्विक एआई सम्मेलन हो चुके हैं। प्रसाद ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत और फ्रांस के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कहा, "यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह ठोस एवं सार्थक है।" उन्होंने कहा कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश भविष्य में एआई के उपयोगकर्ताओं, डेटा सृजन और इस्तेमाल के मामले में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा, "इसलिए उन्हें वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भूमिका निभानी चाहिए।" प्रसाद ने सभी हितधारकों को नयी दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण देते हुए कहा, ''भारत 'एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन को किसी अंतिम बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मंच के रूप में देखता है, जो सरकारों, उद्योग जगत, शोधकर्ताओं, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाकर मिलकर समाधान खोजने और सतत सहयोग के लिए प्रतिबद्ध करता है।